BJYM MAGAZINE

OCTOBER 2021

CONTENTS

3 BJYM Sankalp

4 Message From Sh. J.P. Nadda Ji, Party President, BJP

6 Message From Sh. Amit Shah Ji, Home Minister

7 Message From Sh. B.L. Santhosh Ji, General Secretary, BJP

8 Message From Tarun Chugh Ji, All India BJP Secretary

9 Message From Sh. Tejasvi Surya Ji, BJYM President

10 Sewa Hi Sangathan, Sangathan Hi Sewa

12 #BJYMCares COVID-19 Doctor Tele Consultation National Helpline

13 Redefining India

17 India's demographic sweet spot is real

19 Seva Aur Samarpan

21 सेवा और समर्पण: एक झलक

22 Start up India

23 Government Schemes for the Youth

26 मुस्लिम समाज में जातिवाद और सामाजिक न्याय का सवाल

28 भारतीय पदक विजेता, टोक्यो 2021

33 टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी

42 Cities as engines of economic growth

44 CoWIN: an unheralded success

46 Bad Bank

47 सेंट्रल विस्टा निजी नही राष्ट्र की सम्पत्ति है

49 Women Entrepreneurship in New India

51 The Challenge of India's Urban Development

53 India's New Education Policy 2020 ushers in the dawn of the new era in higher education

Advisory Board

Abhinav Prakash
National Vice-President BJYM

Varun Jhaveri
National Incharge, Policy & Research BJYM

Editorial Board

Aditi Narayani
Saurabh Kumar Pandey

BJYM Sankalp

I believe in the eternal idea of Bharat. In the name of all the martyrs that have shed their blood for Bharat Mata, I pledge to defend the civilizational values of Bharat and territorial integrity & sovereignty of the Republic of India. I pledge to protect all Indians from discrimination, exploitation and oppression from the powers that be. I pledge to build a new India by 2047. I pledge to nurture the spirit of nationalism. I pledge to fight against corruption. I pledge to ensure justice for all Indians. I pledge to protect the environment. I pledge to build a Swachh Bharat & Swastha Bharat. I pledge to build Atmannirbhar Bharat. I pledge to build a new India of prosperity, equality, peace, and harmony.

I shall strive to work for Desh and Dharma.

Vande Matram!

मैं भारत के शाश्वत विचार में विश्वास रखता हूं। शताब्दियों से भारत माता की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों के नाम पर में प्रण लेता हूँ की में सदैव भारतीय सभ्यता और भारत गणराज्य की अखंडता और सम्प्रभुता की रक्षा करूँगा। मैं सभी भारतवासियों को हर परिस्थिति में भेदभाव, दमन और शोषण से बचाने का संकल्प लेता हूँ। मैं 2047 तक एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लेता हूं। मैं राष्ट्रवादी भावना का वाहक बनने का संकल्प लेता हूँ। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लेता हूँ। मैं सभी भारतवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लेता हूँ। मैं पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं। मैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प लेता हूँ। मैं आत्मानिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेता हूँ। मैं समृद्धि, समानता, शांति और सद्भाव से परिपूर्ण नए भारत के निर्माण का संकल्प लेता हूं।

मैं देश और धर्म के कार्य हेतु सदैव तत्पर रहूँगा।

वन्दे मातरम्!

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी

दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

संदेश

भारतीय जनता युवा मोर्चा 1978 से लगातार भारतीय युवाओं में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मैं जब अपने युवा मोर्चा के दिनों को याद करता हूँ, तो बहुत - सी स्मृतियाँ ताज़ी हो जाती हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि युवा मोर्चा भाजपा की एक मजबूत और ऊर्जावान इकाई है। यह युवाओं की एक ऐसी टोली है, जिसमें समाज को बदलने की क्षमता है, भारत माता के लिए खुद को खपाने की तमन्ना है। ऐसे युवा मोर्चा की अनवरत यात्रा को समेटे यह स्मारिका युवाओं को प्रेरित करने वाली तो है ही, साथ ही भविष्य में युवा मोर्चा किस प्रकार से अपने कर्मपथ पर चलते हुए इतिहास के नए अध्याय रच सकता है, इसका सार भी इसमें समाहित है।

भारत में आज के समय में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। ऐसे में अगर वे सही दिशा में चल निकले तो भारत को आगे बढने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। युवाओं के आदर्श और एक ओजपूर्ण व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि, " एक विचार लो। उस विचार को अपना जीवन बना लो और उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा भी देश के युवाओं को इसी राह में बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसे राष्ट्रवादी विचारों से ओत - प्रोत संगठनों की महत्ता स्वतः ही बढ़ जाती है। भारतीय संस्कृति , परम्परा और विरासत के प्रति गौरव - बोध से युक्त होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हुए युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों को करना चाहिए। बदलती वैश्विक अर्थनीति और राष्ट्रीय राजनीति का समन्वय कैसे हो , यह जानना - समझना भी युवाओं के लिए बेहद जरूरी है।

इस समय पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस महामारी का मजबूती से सामना करते हुए अपने नागरिकों के जीवन एवं जीविका को सुरक्षित रखने में हर सम्भव मदद की है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जन - जन की सेवा के लिए जिस प्रकार स्वतः आगे आए और सेवा की एक मिसाल प्रस्तुत की, उसके लिए मैं युवा मोर्चा के कर्मठ अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या और उनकी समस्त टीम का अभिनंदन करता हूँ।

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विगत वर्ष में कोरोना से लड़ाई तथा अन्य समस्याओं के समाधान में किए गए सहयोग को समाहित करते हुए एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके लिए मैं युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों , सदस्यों तथा प्रकाशन मंडल को बधाई एवं शुभकामनाएँ।

जे. पी. नड्डा

(जगत प्रकाश नड्डा)

अमित शाह
AMIT SHAH

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री
भारत
HOME MINISTER
INDIA

संदेश

मुझे यह जानकर अपार प्रसन्नता हो रही है कि '**भारतीय जनता युवा मोर्चा**' द्वारा अपनी वार्षिक पत्रिका 2020-21 का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका में भारतीय जनता युवा मोर्चा की विभिन्न गतिविधियों का संकलन किया जाएगा। निश्चित ही यह पत्रिका संग्रहणीय और प्रेरणादायी सिद्ध होगी।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ मिलकर सराहनीय कार्य किए गए, लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाना तथा आपके द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की सुनिश्चितता करने के प्रयास प्रशंसनीय थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक सुधारों और नए लक्ष्यों के साथ विश्व में भारत को अग्रणी बनाने का संकल्प लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर '**आत्मनिर्भर-भारत**' के इस स्वप्न को पूर्ण करने में देश के युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

भारत एक युवा देश है। मेरा मानना है कि युवा किसी भी समाज में परिवर्तन के मुख्य वाहक होते हैं और देश के युवाओं का राजनीति में रचनात्मक योगदान, सार्थक परिवर्तन लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए अनंत सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रसेवा और विचारधारा के प्रति समर्पित युवा मोर्चा जैसी ऊर्जावान शक्ति हमारे पास है।

मैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों और मेरे तमाम युवा साथियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ एवं पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

(अमित शाह)

बी. एल. संतोष
राष्ट्रीय महामंत्री
(संगठन)

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

03.10.2021

संदेश

बड़े हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पत्रिका का प्रकाशन करने जा रही है। इस रचनात्मक पहल के लिए भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्र प्रेमी युवाओं का एक ऐसा संगठन है, जो सामाजिक जनचेतना को विकसित करने की दिशा में लगा हुआ है। आज के समय में जब बात राष्ट्र के उत्थान की होती है फ़िर स्वाभविक सी बात है कि उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। भाजयुमो भी तत्कालीन दौर में एक ऐसा सामाजिक-राजनीतिक संगठन है, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र हित के मुद्दों पर जन जागरूकता फैलाना है। इन्हीं विचारों से ओत-प्रोत होकर ही यह संगठन समाज के सभी वर्गों को अपने में समाहित करने की पहल सदैव से करता आ रहा है। अभी हालिया दौर में कई राज्यों में जब भाजयुमो की नई टीम गठित की गई। उस वक्त भी यह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिली कि उसमें समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा।

भारतीय जनता युवा मोर्चा नौजवानों एक ऐसा मंच है, जो जाति, धर्म के बंधन से परे होकर राष्ट्र की बात करता है। इस संगठन की नींव कहीं न कहीं संविधान की मूल भावना 'हम भारत के लोग' पर टिकी हुई है और इसका उद्देश्य और कर्तव्य दोनों सिर्फ़ और सिर्फ़ राष्ट्रप्रेम की अलख को जगाए रखना है। इस दिशा में यह संगठन पहले से ही कार्यरत है। कुल मिलाकर कहें तो भाजयुमो नए तरीके से रचनात्मकता और सृजनशीलता को समाज के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है।

आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 'आत्मनिर्भरता' के मंत्र के साथ विकास के पथ पर सतत अग्रसर है और विश्व पटल पर भी अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक ले जाने की दिशा में युवा मोर्चा सक्रियतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
मुझे इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि युवा मोर्चा देश के युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक जड़ो से जोड़ने के साथ उनमें राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ने की अपनी मुहीम को सदैव गतिशील रखेगा।

भवदीय

(बी.एल. संतोष)

तरूण चुग
राष्ट्रीय महामंत्री

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

दिनांक : 02 अक्तूबर, 2021

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 1978 से अब तक अनेक ऐसी नेतृत्व क्षमताओं का विकास किया जिन्होनें संघर्षशील, चिंतनशील एवं विकासशील संगठन को एक नया आयाम प्रदान किया। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रनिर्माण की भावना से ओत प्रोत हमारे युवा मोर्चा के करोड़ो कार्यकर्ताओं ने जिस निष्ठा और सेवाभाव से कार्य किया है वो अतुलनीय है। बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कार्यकर्ताओं ने जिस अदम्य साहस के साथ कार्य किया है वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकाल में मैंने जो सीखा, वो मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में, एक अहम हिस्सा बन चुका है, वो हैं अनुशासन, समर्पण और सेवा। युवा मोर्चा के हमारे सभी साथियों को इन गुणों को सीखने, समझने और अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। भारत इस सदी का सबसे युवा देश है। युवा शक्ति का समूल सदुपयोग किए बिना एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना कठिन कार्य है। आज के समय में युवा मोर्चा जिस तरह से कार्य कर रहा है, उसमें सबसे आवश्यक बात है यह है कि सभी सकारात्मक शक्तियों को केंद्रित करके एक निश्चित लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ना होगा।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा भी समय समय पर युवा शक्ति का आह्वान किया गया है और वे भारत को सबसे सशक्त युवा राष्ट्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। ऐसे में मैं युवा मोर्चा के साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के विजन को एक महोत्सव की तरह युवाओं के मध्य ले जाएं। उन्हें प्रेरित करें कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी विश्वव्यापी मुहिम का हिस्सा बनकर वे भारत को पुनः विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएं। देश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं, असीमित संसाधन है। विज्ञान, कला, साहित्य, चिकित्सा, रिसर्च, सेना, पुलिस, आईटी सेक्टर या राजनीति, जिस भी क्षेत्र के माध्यम से वे राष्ट्रनिर्माण के इस यज्ञ में आहुति करना चाहें, उन्हें साथ लेकर चलें। भारत के समावेशी विकास की नई इबारत लिखें।

युवा मोर्चा के सभी साथियों से मेरी यही अपेक्षा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तम्भ के रूप में कार्य करते हुए मुख्यधारा की राजनीति में निष्ठावान नेतृत्व प्रदान करते रहें। भारतीय राजनीति में भाजपा युवा मोर्चा ने समय के साथ आगे बढ़ते हुए अनेक अविस्मरणीय मानक स्थापित किए हैं। ये अद्भुत यात्रा ऐसे ही जारी रहे......

शुभकामनाएं सहित।

आपका,

(तरूण चुग)

TEJASVI SURYA

Member of Parliament, Lok Sabha
National President, Bharatiya Janata Yuva Morcha

- शुभकामना संदेश -

भारत की राष्ट्रीयता एवं सभ्यता के पुनरुत्थान के लक्ष्य को आत्मसात कर 1978 से भारतीय जनता युवा मोर्चा देश और धर्म के लिए कार्यरत है। हमारे दिग्गज नेतृत्वकर्ताओं के अथक परिश्रम और कार्य के प्रति भावपूर्ण समर्पण ने युवा राष्ट्रवादियों का एक जीवंत परिवार बनाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने असंख्य राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण किया है, जिन्होंने 1978 से भारतीय राजनीति के उद्देश्य को नई दिशा प्रदान की है।

दुनिया में सर्वाधिक युवाओं वाले देश भारत के युवाओं की भूमिका न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को भी सार्थक रूप एवं आकार प्रदान करने में सक्षम है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तकनीकी परिवर्तनों, शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था का परिवर्तन और आर्थिक शक्ति का केंद्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरण के चलते तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि युवा मोर्चा सम-सामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों और वाद-विवादों से जुड़े राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को सार्थक आकार देने में अपना योगदान दे।

इस कार्य हेतु युवा मोर्चा ने देश भर के युवाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करने हेतु एक पत्रिका शुरू करने का फैसला किया है। यह ऑडियो और विजुअल सामग्री पर विशेष ध्यान देने वाली एक ऑनलाइन पत्रिका होगी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर लेखों के अलावा नीति निर्माताओं, पार्टी नेताओं, उद्यमियों और युवा कार्यकर्ताओं के वीडियो साक्षात्कार और पॉडकास्ट होंगे। यह युवाओं तथा राष्ट्र के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर युवा मोर्चा के वैचारिक और राजनीतिक रुख को संप्रेषित करने का भी एक मंच बनेगा।

युवा मोर्चा अपनी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान पत्रिका का एक विशेषांक भी जारी करेगा जिसमें चुनिंदा लेख और साक्षात्कार होंगे।

युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल की पहली राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में पत्रिका के शुभारंभ के साथ हम युवा प्रतिभाओं को सही दिशा देने के मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये युवा ही 2047के भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं।

मैं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अभिनव प्रकाश और पत्रिका की टीम को बधाई देना चाहता हूं तथा राष्ट्र निर्माण के इस सार्थक प्रयास हेतु शुभकामनाएं देता हूं।

L. S. Tejasvi Surya

तेजस्वी सूर्या
03.10.2021

Sewa Hi Sangathan, Sangathan Hi Sewa

The heart wrenching memories of the second wave of COVID 19, that hit every corner of the country, have still not faded from the people's mind. Neither have they forgotten the collective efforts and benevolence of the society in fighting the pandemic during these tumultuous times.

In Bharatiya civilization, it is always believed that whenever an evil is overpowered, the good takes charge in many forms to relieve mankind from sufferings. Similarly, when the corona virus was challenging human existence, lakhs of courageous volunteers stepped up to offer help for the sake of mankind.

The second wave appeared to have crested in Maharashtra, Delhi and Chhattisgarh, spread like wildfire in the entire country within 7-10 days. On one side infections were multiplying in lakhs, the healthcare system saturated within a week on the other side. A further challenge during the peak of the second wave was the sudden decrease in the oxygen level of patients, and shortage of requisite proper ventilation support. With no sure shot medicinal treatment, the shortage of prescribed medicines worsened the situation in many parts of the country.

Call for Action

In such difficult times when thousands of citizens, and social groups were coming forward to extend their Sewa, how was the nation's largest youth political group not supposed to do anything? Reckoning the clarion call of BJP National President Shri JP Nadda ji for the Sewa Hi Sangthan Abhiyan, the BJYM National President Shri Tejasvi Surya called on all the young karyakartas to take the baton ahead and leave no stone unturned to help the needy ones.

Number of oxygen Concentrators Arranged	7,421
Number of oxygen Cylinders Delivered	66,373
Number of people helped in getting Vaccinated	14,50,534
Number of Karyakartas engaged in the Vaccination Campaign	36,344
Number of Cremations with the help of BJYM	23,544
Number of 'Namo COVID Care Centres' set up	301
Number of Beds in the 'Namo COVID Care Centres'	4,755
Number of Face Masks Distributed	36,84,436
Number of Food Home Deliveries	20,06,661
Number of BJYM Ambulances	1,160
Number of Sanitizers Distributed	13,27,505
Number of Calls Received on State & District Helpline numbers	1,46,052
Number of Ration Kits Deliverd	5,38,237

The cadre which is excellently trained and acquainted for ground activities and communication with the public faced a new obstacle altogether. Real challenge was carving out ways to help maximum people and mitigate the possibilities of spread at the same time. The situation was very dynamic and demands were changing rapidly. There was no time to forecast and plan the requirements. The movement was built and curated as per the decentralised requirements at the national, state, district, mandal and booth levels.

The combination of on-ground karyakartas, war-room karyakartas and technology was paramount. There could have been no single formula to reach out and help the needy ones. It must be admitted that social media, mainly twitter and instagram played a crucial role in raising as well as tracking the SOS requests.

From Mask Distribution to Covid Care Centres

Continuous vigilance and learnings by BJYM karyakartas and leadership played a crucial role. The regular review meetings, consultations and replication of best practices ensured seamless work. There were groups of karyakartas camping in outside collectorates, hospitals and medical shops day and night and another set of karyakartas on laptops and mobile phones, tracking each tweet and making more than 300-400 phone calls every day. It is evident from the twitter threads that everyone - celebrity or commoner, rich or poor, known or unknown, was being treated equally.

The movement which started with distributing masks and food to the needy ones was setting up covid care centres in different parts of the country within 15 days. The great work done was inclusive of, but not limited to the following

Power of Sangathan

One of the primary reasons for the massive success of BJYM Cares was swift and effective communication amongst the volunteers. This is the magic of the unique organisational structure of the morcha and the party. No time was wasted in streamlining the processes or circulating a toolkit to the volunteers. The discipline of the party and commitment to respond to every request were enough to make it a colossal sewa abhiyan.

In our experience, we have never witnessed so many heroes emerging out of a single movement at the same time and every one was equally dedicated and not less courageous than others. The power of Sangathan was felt when an SOS to find a hospital bed in Kerala was raised by a Karyakarta in Chhattisgarh, thereon forwarded by Karyakartas placed in Delhi and a quick response was received from the BJYM Kerala President that a bed for the said request has been arranged. This all exercise was completed in less than an hour.

Success and Failures

We believe that when you extend your services with honesty, there are no parameters of success and failure. We succeeded every time when a life was saved, a unit of plasma was arranged, oxygen was made available or even an empty stomach was fed in such situations. And we lost every time when we were not able to help the needy ones.

- As the situation has subsided, it is time to realise that when many people were involved in blackmarketing and making undue profits or fabricating national news for political advantages, there was not a single proven allegation of irregularities or fraudulent actions by BJYM karyakartas across. We must proudly thank the founders and leaders of the sangathan for creating such a platform for the nation. In these testing times, we stood true to our slogan- "Party with a difference".

AUTHOR: - SUYASH PANDE

#BJYMCares COVID-19 Doctor Tele Consultation National Helpline

With the country experiencing a second wave of COVID-19, it had once again come together to battle the pandemic. The Central Government, under the leadership of Hon. PM Shri Narendra Modi Ji was constantly coordinating with the State Government in implementing a strong response to COVID-19 at all fronts. In the first wave, the Government increased testing capacity, production of PPEs and swabs, and availability of COVID-19 beds. At the same time, the Government introduced various technological solutions to assist citizens in managing COVID-19. In the second wave, the Government focused extensively on ensuring a higher coverage of vaccination and availability of oxygen, essential drugs and availability of COVID-19 beds.

As a party, BJP, in the last 2 years, throughout both the COVID-19 waves, has worked relentlessly in serving citizens and helping them come out of this crisis. Our Karyakartas, across the country, have been point of contacts for their communities wherein they have served the communities. Whether it was helping citizens from getting access to doctors or hospitals or supporting citizens with provision of essential supplies such as ration and basic medicines, our Karyakartas have worked round the clock in helping the communities and country. Our Karyakartas even served food in the isolation wards of many COVID-19 hospitals, procuring essential supplies for citizens and helping citizens get vaccinated. As the cases soared, there was an increase in the total cases requiring hospitalization. This significantly pressurized the health system of the entire country.

Given the fact that around 98% of COVID-19 patients did not require hospitalization, it was critical that patients were empowered with timely information on managing COVID-19 through home quarantine. This helped citizens in managing their symptoms through home quarantine thereby reducing the need for hospitalization. To ensure the provision of information on managing COVID-19 through a single telephone call, BJYM launched a multi-lingual COVID-19 doctor tele consultation national helpline. The launch was done by the Hon. President of BJP, Shri JP Nadda Ji.

The purpose of the helpline was to connect citizens with doctors who would provide information related to managing COVID like early and mild symptoms of COVID-19. In this helpline, citizens from any part of the country can call the national helpline to seek medical advice from doctors for their symptoms. The helpline catered to multiple languages to ensure that it can assist citizens across the country. During the call, the patient could mention their symptoms and receive advice from the doctor. Further, after the call, the helpline sent caller information about their respective state BJYM Helplines. Citizens could then call the state helplines and seek help from the BJYM karyakartas based on the doctor's recommendation. Our BJYM volunteers then helped the patients in procuring medicines, essential supplies, food etc. So, in all, this was not just a one-way helpline but a complete system for assisting citizens across the country.

The helpline was developed and operated in partnership with various technology startups headed by young entrepreneurs. The entire helpline was developed in a record-breaking time of less than a week. This is a great example of how young citizens can collaborate to serve the country in such crisis.

The helpline turned out to be a huge success. In terms of numbers, more than 1600 doctors were onboarded and around 46,000 minutes of doctors consultation through 40,000+ calls was provided through the helpline. The helpline received testimonials across the country. A couple of them are mentioned as below.

- Mr. Sri Krishnan expressed his gratitude by saying, "Yes. Million Thanks to Tejasvi Surya. One in my team had all symptoms. We couldn't get a doctor despite multiple attempts. It was the BJYM's helpline that helped. A doctor came online, symptomatically confirmed and started on medicines, advised test 4 records."
- Ms. Sneha appreciates the honest efforts by saying, "Thank you so much for the helpine. After registering I got a prompt call from the doctor who answered my question to satisfaction, it is rare to find such promptness."

The helpline was also widely promoted by key society influencers. "If you have any symptoms of corona, you need not worry, sitting at home, you can dial at BJYM doctor helpline and reap the benefits of its service." Said Sri Pema Khandu ji, the Chief Minister of Arunachal Pradesh. "Do you have COVID-19 symptoms? Do not worry. Now you can get a doctor's consultation, free of cost, at home. You can call on BJYM's doctor helpline number.", said Smt Khushbu Sundar, Actress.

The BJP and BJYM, again through this innovative initiative, showed its relentless commitment to serving the country in perhaps the most difficult time and displayed its ideology of always keeping the nation first.

Redefining India

An open civilisation rejecting old monolithic constructs

OCTOBER 7TH MARKS THE DAY Prime Minister Narendra Modi completed 20 years as the head of a government. It includes his transformative 13 years as the chief minister of Gujarat and seven illustrative years as the incumbent prime minister. These two decades have seen the transformation of India as a nation and as a civilisation. Modi is both a symbol of and the driving force behind the emergence of New India, which is more rooted and confident in its civilisational antiquity and futuristic in its vision.

The Republic of India emerged from a turbulent period of repeated waves of invasion, settler colonialism and imperialism. The indigenous resurgence started before the British period during the Maratha century when the rule of foreign dynasties was rolled back on large parts of the Indian subcontinent. The British conquest of India violently disrupted this resurgence. It is often discounted how brutal British rule was and how violently they conquered and subjugated India. Two centuries of British rule in India were two centuries of hunger and famine and two centuries of armed uprisings by the masses every decade. Following the sacrifices made by countless revolutionaries and freedom fighters, the spectre of the Indian National Army and the naval uprising of 1946, the British rule finally ended. But then imperialism is not just about the physical subjugation of a country. It is also about cultural, social, institutional and knowledge aspects of the society and the polity.

British rule formally ended in 1947, but the Raj continued to linger and even thrived among the remnants of the colonial elite and order. The old agrarian relations instituted under British rule survived the uneven tenancy reforms. Flawed economic policies ensured that India failed to industrialise and urbanise, stifling the key driver of economic and social change. The political alliance of the English-speaking urban elites and feudal elements in the countryside blunted the promise of the Constitution and democracy for the majority. Life went on listless for the vast majority of the people as before, full of deprivation, poverty and lack of socioeconomic mobility.

The core task of the postcolonial Indian

state should have been the rejuvenation of the Indian nation and the renaissance of Indian civilisation. And the key to this task was the rapid socioeconomic transformation on the back of industrialisation and modernisation. The economic uplift of the masses and social emancipation after centuries of foreign dominance was the historical task of the state. But instead, we deluded ourselves into chasing alien constructs of the secular-socialist paradigm. The state and government became a vehicle for perpetuating the old elite rule and patronage to the cultural commissars tasked with whitewashing history and creating an alternate reality to "re-engineer" society into their imagined ideal state. The result was decades of economic stagnation, social unrest and a worsening strategic and security environment.

The democratic upsurge in the anti-Emergency movement and later economic reforms provided a respite from a seemingly endless dystopia presided over by Congress the hegemon.

Economic reforms proved to be a pivotal moment in India's history. It put India on a new trajectory of growth to which the National Democratic Alliance Government gave a further fillip under the prime ministership of Atal Bihari Vajpayee. It disturbed the diurnal certainties of life and caused a churning, continuing from which a New India is finally emerging. Millions of people, especially the marginalised communities, fled the villages with their social and political bondages to the burgeoning urban centres in one of the greatest migrations in human history. It was both an act of desperation and an act of liberation. A new class of people emerged from smaller cities and towns that were neither part of the old landed agrarian elite nor the bureaucratic and political patronage system of what is derisively called Lutyens' Delhi. It was this class that distrusted the old elite and yearned for change in the political guard. These middle and neomiddle classes became part of the democratic uprising that in 2014 swept aside the old political certainties and cold arithmetic of opportunistic caste and communal calculation. Narendra Modi had won the largest democratic mandate in human history. A feat he would repeat in 2019.

So, what does the rise of Narendra Modi symbolise?

Economic transformation, democratic deepening, social assertion, rejuvenation of the Indian nation and renaissance of the Indian civilisation. He is both a product of the churn and an architect of New India. He has been a relentless moderniser in his entire tenure, first as chief minister and then prime minister. He has emphasised economic growth by embracing the markets and consigned the old samajwadi obsession to the dustbin of history, where it rightly belongs. By championing entrepreneurship, reinstating profit as a legitimate goal, and celebrating businesses and industry, he has caused a shift in the political culture of India in favour of economic growth and prosperity.

The debate has shifted from removing poverty to creating prosperity. The opposition may mock his plank of vikas but is forced to talk about development and claim that it can deliver better than Modi. Modi has embarked on an arduous path of accelerating the modernisation of the Indian economy, the Indian state and Indian institutions. Over the last year, he has enacted the biggest set of economic reforms ever, touching every sector of the economy from agriculture to manufacturing to labour laws to tax laws. And unlike the 1991 reforms under duress, these reforms are born of conviction. His push for digital India, universal access to digital public goods and digital sovereignty is guided by a vision of the future. He has pushed the unified legal and administrative structures, such as the Goods and Services Tax, "One Nation, One Ration Card", etcetera, which seek to strengthen the Indian state and modernise its apparatus for the 21st century by empowering the people.

Modi has laid great emphasis on infrastructure development. Road and highway construction are at an all-time high; the railways are getting modernised; Bullet Trains are being introduced and reaching hitherto untouched corners, especially in the frontier regions. Waterways are being revived, and air connectivity is expanding like never before. Why is all this important? We often forget that infrastructure is one of the key factors that have driven nationalism and civilisational consciousness. When the Sui dynasty built the Grand Canal, north and south China were brought into closer cultural and social embrace. The Roman roads were transmitters of the Roman civilisation and Roman identity in the farflung areas of the empire. Railways and highways in the modern period reduced distance, spurred migration and enabled economic integration, thus playing an important role in the rise of the modern nation. The rapid expansion of infrastructure is leading to the rise of an even stronger common Indian identity where the difference between local and national is getting blurred with each kilometre added to the expressway or new tracks laid in the Northeast. Modi is redefining what it means to be an Indian simply by enabling more and more Indians to fly for the first time through policies such as the Udan Yojana.

VS Naipaul rightly called India a "wounded civilization". Repeated invasions and colonisation by various Central Asian tribes dislocated society and brought wanton destruction upon the sacred sites. Such has been the scale of destruction that hardly any temple structure older than 200 years can be found in north India. Even after Independence, these historical wrongs were not corrected, barring in exceptional

cases such as the Somnath temple in Gujarat. Nor was any serious attempt made to repair and reconstruct the sacred sites to restore them to their former glory. Everywhere one went, there were temples in ruins or occupied by alien structures. Most of the temples and sacred sites that were operational were in a dilapidated state. Prime Minister Modi is the first ruler after Shrimant Ahilyabai Holkar to build, repair and renovate temples on such a large scale. Several famous temples in Ayodhya, including ghats of Saryu, were rebuilt by the sage queen. And today, after 500 years, the Ram Temple is reborn. Kedarnath and Kashi Vishwanath are being renovated for the new era. Where mocking and targeting temples was once common, the ascendance of shakti-upasak Prime Minister Modi has compelled the deracinated secular leaders to do a temple run. Sacred cities and places such as Varanasi and Vindhyanchal are undergoing transformation. And with these, the cultural, spiritual and civilisational essence of Bharat is being reclaimed one brick at a time.

One of the core issues in the rejuvenation and renaissance of India has been a fractured society with deep faultlines running across caste lines and persistence of discrimination and marginalisation. Economic modernisation and industrialisation pursued by Modi weaken the boundaries of caste and undermine the structure that sustains the caste system. But it is not sufficient, and conscious efforts in the realms of society, government and polity are equally important. It is important to remember that Modi started his activism in the Sangh Parivar, which, rooted in Hindutva, inherited the legacies of the Hindu proto-modernity of the early modern period and contemporary social and religious reform movements to imagine a modern nation. Rising above the distinctions of caste and community has been one of the core concerns of the Sangh Parivar. It is the worldview reflected in the policies and working of Prime Minister Modi. He has launched massive welfare schemes for the poor and the marginalised communities. From free housing to free healthcare to free gas cylinders, his schemes are the wildest dreams of doctrinaire leftists in Western countries such as Bernie Sanders and Jeremy Corbyn. But unlike the old guard, Modi is known for ensuring successful implementation of these schemes. But most importantly, he has based these schemes on objective criteria. Caste operates on the ground by excluding weaker castes from access to state resources and schemes. India has failed to achieve even basic education and healthcare because the implementation of these policies was mediated through local power structures that invariably depended on old social structures. It meant that most of the benefits were captured by dominant caste leaders. It is here that Modi has acted as a disruptor par excellence.

He has not only ensured public provision of private goods to the poor but made these either universal or dependent on a clearly defined criterion such as the Socio-Economic Caste Census, 2011. And by doing so, he has undermined the old patronage model of politics where a person would benefit if her caste supported the party in power. The old patronage model created a “politics of unfreedom” for the weaker castes, especially the non-dominant Other Backward Classes and Dalit castes, who are now free of the tutelage of the dominant castes in accessing government schemes and benefits. It is no surprise that they have rallied behind the prime minister and his party, which has undermined old caste politics that thrived on promoting the widening of the social divide. This new model of bringing people together and welding them into a united political bloc without appealing to base caste instincts was always critical in healing the social divide and laying the foundation of a stronger national and civilisational rejuvenation.

Social inclusion and representation without factious competitive caste politics is the new paradigm ushered in by Modi. This new paradigm was visible when as chief minister of Gujarat, he started a training programme for priests from Dalit castes. It was visible when he formed the most inclusive and representative council of ministers ever in India. There can be no restoration of pride in the Indian spiritual traditions and civilisational narrative unless social equality and harmony are at the cornerstone of the futuristic vision of India. And under Modi, we have seen that vision in action and not just the usual political rhetoric of the past.

In the “Idea of India” of the old elite, the identity of India was defined in opposition to British imperialism. It was an identity supposedly born of the struggle against British rule, which was ascribed to one party and family in the version of the court historian patronised by successive Congress governments. The role of thousands of revolutionaries and the contribution of various castes and communities were sidelined. We were told that unless we believe that India owes its existence to the anti-British struggle led by Congress and pledge our allegiance to its monolithic view of India, the existence of India will come under threat. But as successive generations of Indians moved away from the direct experience of the anti-British struggle, they found it more and more difficult to relate to this arcane “Idea of India”, not the least because it was an artificial construct that didn’t gel with the social and civilisational memories of the society. Disenchantment with the narrative of India created the void which was being filled by far-left ideas and wokeness flowing from the liberal arts departments of American universities.

THE RISE OF Modi has corrected this anomaly by firmly rooting the identity of India in its civilisational history. India is not merely a postcolonial state. India is not merely a modern nation supposedly

created in the process of anti-British struggle. India is the world's oldest living civilisation. And at present most of the geographically contiguous parts of this civilization are united under a single polity, and this political unification derives its justification from a shared civilisational heritage. This older, grander sense of Bharatvarsha has been revived in the popular imagination by Prime Minister Modi. It is reflected in his speeches, in his symbolism and in his action. When in his speech at the UN General Assembly, he asserts that India is the mother of democracy, he is invoking the ancient republics of Bharatvarsha, religious sanghas, village councils and various spiritual traditions that advocated and practiced democratic, collective decisionmaking with social and gender representation. When he becomes the first prime minister to visit the Ram Mandir in Ayodhya, he affirms that the"Idea of India" is much older than the modern history of the anti-British struggle. When he takes foreign dignitaries to the ghats of Varanasi, he is mainstreaming the antiquity of India that is Bharat into the international relations and strategic discourse.

Under Modi, India is reclaiming its natural identity as an open, plural civilisation by rejecting the old monolithic constructs seeking to impose a manufactured version of history and identity. He has refocused the Indian state on its historical task of the rejuvenation and renaissance of the Indian nation and civilisation by accelerating economic transformation, infrastructure development and social inclusion. As an administrator, he has proven himself to be the great moderniser who seeks to propel India into the future by equipping it with a modern state apparatus and legal framework for the 21st century. As a politician, he has swept aside the timidity and apologia that the Indian political class felt when owning its identity and practising its traditions. What we see before us is the architect of New India and the rise of a civilisational state.

AUTHOR: ABHINAV PRAKASH SINGH.
(THIS ARTICLE WAS FIRST PUBLISHED IN OPEN MAGAZINE ON 11/10/2021)

Modi at the Badrinath temple in Uttarakhand, May 2019

India's demographic sweet spot is real

India and China both had their working age fraction bottom out at the same level in the 1970s, but China's has already peaked in 2015 and India gets 30 years more.

India's long term per capita growth rates (say over 10-15 years) are dependent on three factors:

- Demographic and human capital trends
- Global technology and macro trends
- Indian policy and political trends

India's GDP graph shows that a trailing 10 year average per capita growth rates for 2020 would be just short of 6%, for 2010 it was around 5%, for 2000 it was just short of 4%, for 1990 it was around 3%, and so on. It seems that India's per capita real growth rates have been increasing at about 10 bps per year since the 1970s (and the rolling average shows a clear trend starting around 1980). Just going by that, India's growth over the next 10 years in terms of real GDP per capita is likely to be 7% or so. Add a population growth rate of slightly less than 1%, and you have a total growth rate of 8%. Of course, linear extrapolation by itself is not necessarily correct. Which is why we have to go much deeper with demographics.

The most important graph to understand per capita growth trends from a demographic lens is as below, which is the fraction of India's population that is in the 25-64 age bracket that roughly corresponds with the peak working age for a vast majority of people.

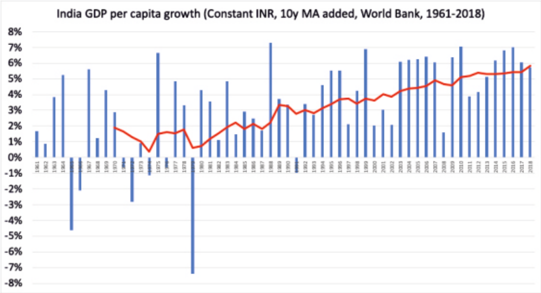

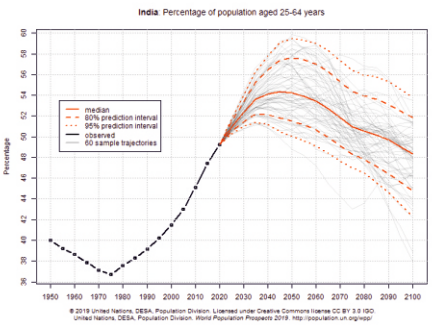

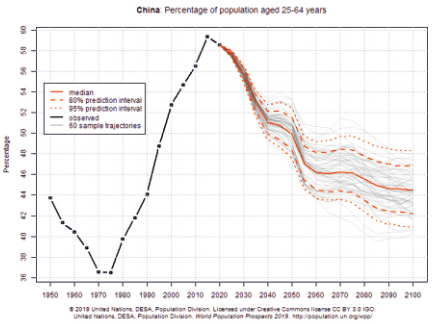

It is indeed very interesting that just around the time India's per capita growth rate started rising in the late 1970s on a sustainable basis, India's working age population fraction bottomed out at about 37% and is now around 49%. India should continue growing faster in terms of per capita growth rates ceteris paribus till the 2040s when the ratio peaks around 54%.

Interestingly, China also saw this ratio bottom out in the 1970s and also around 37%, but it increased much faster than India (reached almost 60% around 2015) but is already declining as shown below. That may help partially explain China's faster growth in the last 40 years as well as its recent slowdown.

While the ratios are key, especially for per capita growth numbers, let us roughly have a look at what that would mean for the aggregates. India will have 200 million more people than China in the 25-64 group (~900M vs ~700M) by the 2040s even as the 'below 25 + above 64' populations would be roughly the same for both at ~700M. That is a lot less weight to carry, in economic terms if not sentimental terms, over the next generation for India.

Back to the working age ratios - why are they so important? Because they seem to determine savings and investments (though in the short term they are pro-cyclical) as seen below in the case of India's Gross Domestic Savings as % of GDP, and hence ultimately growth.

The difference between “working age ratios” and “working ratios” is that of those who are in the relevant age group but do not “work”.

But often in a country like India that would include home makers that do work very hard, just that it is not counted. For example, if X tutors Y's children and Y takes care of X's old parents that is counted as “working” but not if the two activities happen within their respective

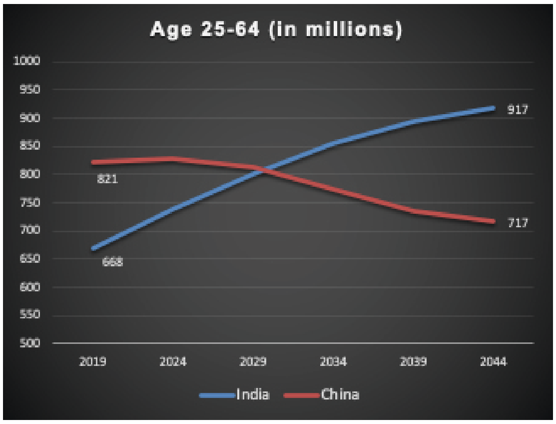

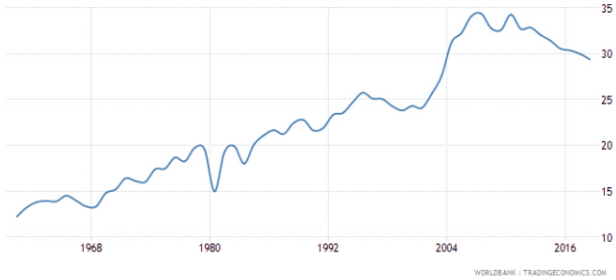

homes itself.

What is relevant perhaps a bit more then is the dependency ratios and the human capital formation, at least compared to the formally reported working populations. Not that the latter is not important by itself as more women in the “labour force” (ratio follows a U-shaped curve with India's adjusted female labor force participation having bottomed out in recent years) besides the socio-economic benefits, is likely to be strongly correlated with faster growth. But it is difficult to tease out that correlation vs causation (whereas with overall population and age numbers it is less so.)

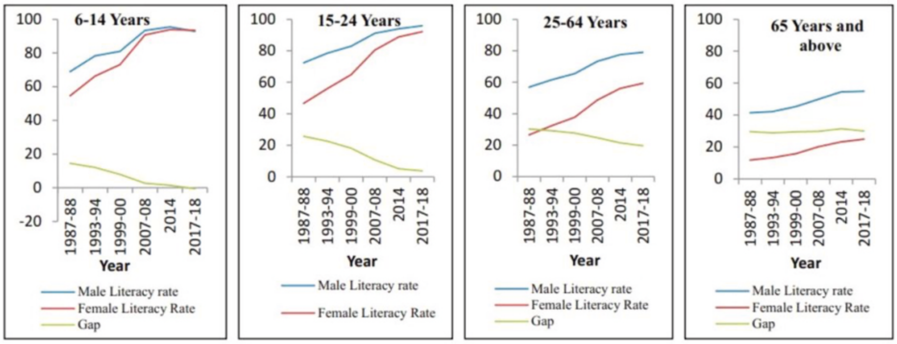

Source: National Sample Survey @ Observer Research Foundation's India Data Labs

Going back to human capital, India's literacy rate has increased consistently - especially for the young (and for females), and while serious quality issues certainly remain basic education access is not that significant an issue as it once was.

Pre-teens have near universal literacy and no difference for boys and girls, and even for the 15-24 demographic we are fast approaching universal literacy. Higher education enrollment rations are also improving but not as well as China's (as the graph below shows.)

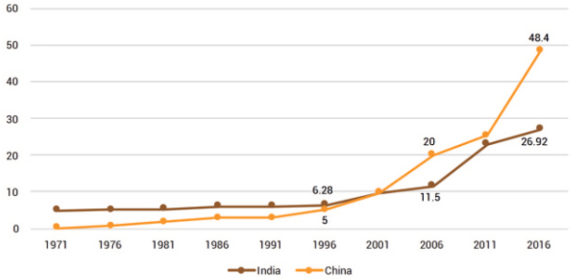

Yet while quality is an issue here as well, negative or no growth in inflation-adjusted starting salaries for Indian IT MNCs over the last one or two decades shows that human capital is surprisingly not a bottleneck for now with respect to entry level white collar service jobs (though it is a bottleneck for more complex roles such as product development and senior management, although one must add large entry-level employers have also started their own training programs due to severe lacuna in our various curricula.)

On the public health side, the infant mortality rate has also been falling (so has maternal mortality rates etc.) Also, sanitation coverage has dramatically improved in recent years (as shown in the graph below) along with electricity access (at the village, not house level as of now) and rural roads to expressways, and the next target for mid-decade is piped drinking water across all homes. But let us not delve too deep into that as that would come under the Indian public policy post of me trying to figure out the long term sustainable growth rates for India.

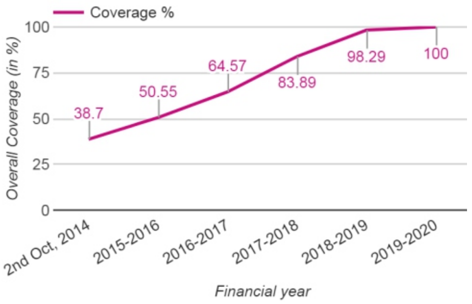

The aim here is just to show not just the quantitative aspects of the Indian demographic sweet spot, but that the qualitative aspect in terms of basic social infrastructure, while still far from ideal, is not as bad as it is sometimes depicted.

In short, from a demographic standpoint India is likely to see more of the same for the next 20-30 years as it has over the last 30-40 years. Remember, the increasing 10 year rolling average of GDP per capita graph shows almost no clear break or jump because of the 1991 reforms but the dependency ratio having peaked in the 1970s is a clear correlation. Human beings, including “experts” have a tendency to obsess over things they deem important - liberalisation, which they can direct with their jargon - as opposed to blessings or faults that if not “in our stars” then have been at least baked into the cake decades ago.

Of course, economists still worry about whether India can be the “next China” (or even a fraction thereof) in terms of manufacturing exports and so on, but who really predicted in the 1980s that over the next generation it would be computers and a thing called “the Internet” that would directly or indirectly create large parts of the Indian middle class.

AUTHOR: HARSH GUPTA MADHUSUDAN

Seva Aur Samarpan

Celebrating Modiji's 20 years of public service

As Prime Minister Narendra Modi turned 71 on (September 17), the Bharatiya Janata Party (BJP) launched a mega 20-day public outreach, 'Seva aur Samarpan' Abhiyaan. This programme continued till October 7 to mark Shri Narendra Modi's 20 years in public life, including the period when he served as Gujarat chief minister. BJP President Shri JP Nadda kick-started the Abhiyan and in his greetings hailed Modi as the "most popular leader of the world", adding that the PM is "dedicated to the progress of the most deprived person in society and symbolises foresighted and decisive leadership besides tireless efforts".

The 20-day-long 'Seva aur Samarpan Abhiyaan' was conducted under the guidance of BJP National President Shri J. P. Nadda and BJYM President Shri Tejasvi Surya. As part of the campaign, every district unit of the BJYM organized a unique Nava Bharat Mela publicizing the work of the PM Shri Narendra Modi's government over the last 7 years. The campaign also comprised of cleanliness drives, blood donation camps and quiz contests.

While addressing a large public gathering and kick starting the nationwide 21 days campaign - 'Seva Hi Samarpan' at Karnavati Club in Ahmedabad on the occasion of birthday of our Hon PM, Narendra Modi, BJYM President Shri Surya said: "The PM's birthday, which falls on September 17, is a day we spend in service. October 7, the day he assumed office as CM of Gujarat, reminds us of his complete dedication to the service of our nation and its people, a quality that has been a feature of these 20-years in Shri Narendra Modi Ji's life."

The 'Seva aur Samarpan Abhiyaan' was carried out in all the districts across India, and various programs commemorating the same was organized at the District, as well as the Mandal level by the BJYM karyakartas. The highlight of the campaign were the district-wise 'Nava Bharat Mela', which successfully showcased the emergence of a 'New India' under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji. It also highlighted the various schemes undertaken by the Modi Government in the past seven years ensuring the upliftment of those who had been forced to live their lives in the margins. Talking about the first time ever organized – Namo Quiz, Shri Tejasvi Surya said that "the NaMo quiz is an innovative method to understand the awareness about the government's schemes in the youth, especially students. I hope all of them had fun participating in these contests." An innovative and interesting approach to spread awareness amongst the youth of our nation.

In addition to this, the State units were asked to put up stalls in collaboration with the Common Services Centres to facilitate registration for all citizens who wish to enroll in various central government welfare schemes, which was fantastically undertaken by all the state teams in their respective states, thereby benefitting thousands of common men. Stalls celebrating local handlooms and handicraft products, paintings, arts, traditional food, organic produce were also set up to champion the cause of #Vocal4Local.

Laying emphasis on the core values of our party, i.e. "believing power to be merely a medium for service in politics", Bharatiya Janata Yuva Morcha National President, Shri Tejasvi Surya said - "With the Seva Samarpan Abhiyaan, the BJYM draws inspiration from the work ethic of Prime Minister Shri Narendra Modi and is continuing its service and empowerment of the lives of people. The BJYM is organising Blood donation camps across the country to collectively donate as many units as possible for the needy. I am thankful to all the donors for contributing to saving the lives of people."

In Jammu and Kashmir, the BJYM karyakartas organized 3 days 'Nav Bharat' mela in all the 17 districts of their state to showcase the achievements and tireless efforts of our government under the exemplary leadership of PM Modi. Taking a Digital and Mobile approach, we witnessed 'Nav Bharat mela on wheels' across the state of Karnataka. All heads turned towards this moving baton and nodded in consent and respect for the valorous steps taken by our government since 2014. In Haridwar, Uttarakhand also, we hosted an eventful exhibition in

the biggest mall, inaugurated by the State President of BJP in the presence of National General Secretary BJYM.

In addition to this, Quiz contests and blood donation camps were also conducted at district levels by BJYM karyakartas across India, and special stalls were set up to encourage people to download NaMo App, which would help them communicate with the Hon'ble Prime Minister directly and also keep them posted on the various schemes and welfare measures being undertaken by our government. The quiz contest proved to be a unique way of testing and spreading awareness about the government's schemes in various sectors. The Yuva of today is the carrier of information and should be aware of the many schemes that the government is coming up with on daily basis to make the best use of it and also help each other in growing cumulatively.

Joining the national celebrations of the 75th year of India's Independence, BJYM karyakartas celebrated "Azadi ka Amrit Mahotsav" in which youth were encouraged to visit sites related to the Independence Movement in their respective districts. The family members of such respected martyrs were honoured in a humble way by our party karyakartas. We successfully reached out to these families in person and spent some light moments to recall the bravery of our Martyrs.

BJYM karyakartas observed the birth anniversary of Pandit Deen Dayal ji on September 25th through the initiatives undertaken by Modi Government to serve the poor and underprivileged. The principle of Antodya given by Pandit Deen Dayal ji is a guiding light for all the karyakartas of BJYM. BJYM karyakartas also enlightened the beneficiaries and the public about Modi Ji's special focus on Antodya. Now, the communities have themselves come forward to spread a word of the various benefits of Government's schemes.

Another extremely important day that was celebrated under the 'Seva aur Samarpan Abhiyaan' by BJYM karyakartas was Mahatma Gandhi Jayanti on the 2nd of October. Inspired by the motto of 'Swatch Bharat, Sundar Bharat', on this day, "Swachhta Se Samman Abhiyaan" was organized across India by BJYM karyakartas under the leadership of Shri Tejasvi Surya. To build a stronger association of the youth with the cultural hotspots of the nation and also instill a sense of pride among them, BJYM karyakartas, environmentalists and public also organized cleanliness drives and saplings plantation drives at 71 different locations consisting of shaheed smaraks, prominent rivers, and places of worship of the respective state.

सेवा और समर्पण: एक झलक

भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान के तहत हरियाणा में भाजयुमो ने 17 से 19 सितंबर तक प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किये गए। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में 74 रक्तदान शिविरों में 5181 रक्त की यूनिट एकत्र की गई। रक्तदान शिविर के साथ ही साथ हजारों कि संख्या में लोगो को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई। इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश भर में 20 हजार से अधिक युवाओं से युवा मोर्चा के सदस्यों का सीधा जुड़ाव व संवाद हुआ। गुरुग्राम जनपद इस मामले में शीर्ष पर रहा जहां 13 रक्तदान शिविरों में 1014 रक्त यूनिट एकत्र किए गए। पानीपत में 5 शिविरों में 854, करनाल में 5 शिविरों में 343, सिरसा में 5 शिविरों में 327 व पलवल में 4 शिविरों के माध्यम से 195 रक्त यूनिट एकत्र किए गए।

उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सेवा और समर्पण अभियान के तहत अंत्योदय कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सभी 31 मंडलों में अंत्योदय कार्यक्रम के तहत कुल 68 स्थानों पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अभियान में कुल 6988 लाभार्थी उपस्थित व लाभान्वित हुए। कार्यक्रम से पूर्व सभी 31 मंडलों में एक एक संयोजको की नियुक्ति कर उन्हें दायित्व सौंपा गया व कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। ज़िले में अंत्योदय अभियान की मूल भावना जो लाभार्थियो से संवाद स्थापित करना था, उसे जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया. जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया. यही अंत्योदय के विचार के जनक पंडित दीनदयाल जी को युवा मोर्चा द्वारा सही मनाये में श्रद्धांजली हैं.

माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार -
यमुनानगर जिले में जाकर रक्तदान शिविर का जायजा लिया
साथ में जिला के युवा मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे।

माननीय मुख्यमंत्री जी
फोटो परिचय: गुरुग्राम रक्तदान शिविर में रक्तदान युवती से
बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी।

माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी
फोटो परिचय: गुरुग्राम में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान
शिविर में रक्तदान युवक को नेक कार्य की शाबाशी देते हुए
प्रदेश अध्यक्ष श्री औम प्रकाश धनखड़ जी।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जी
फोटो परिचय : कैथल में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान
को बैज लगाकर करते हुए प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल
विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी।

Start up India

The Namo government has been successful in developing a robust start up ecosystem in the country which currently ranks third in the world for nurturing innovation and providing platform to budding entrepreneurs. We all are aware of the fact that many billion dollar business ideas fail to reach us due to lac of critical funding required in the formative years of start up for prototype development, product trials, market entry and commercialization. Startup India Seed Fund Scheme recently notified in January 2021 enables the startup applicant in availing seed support in the form of grant and debt/convertible debentures upto Rs. 50 lakhs. The government has been giving these start-ups the necessary nutrition to get on with value creation with the minimum of government interface. So, there is to be self-certification when it comes to compliance with six labour and three environmental laws—since the start-ups are primarily based on tech, this is to be done through a start-up app. Moreover to resolve the angel tax issue, startups are exempted from scrutiny in valuation of share premiums. Startups with turnover of less than Rs 25 crore will be eligible for getting 100% tax rebate on profit for a period of three years in a block of seven years. All such policies whether regulation based or financial based aim for motivating the youth towards entrepreneurship, such rebates and exemptions have proven themselves as india currently houses 27 unicorns (billion dollar startups) which is a massive leap for a country which opened its gates to globalisation just 4 decades ago.

Modi Govt's policies are Incentivizing entrepreneurship as a means to limit brain drain and strengthen our domestic industrial infrastructure is a need of the hour. majority of top brass posts in MNC'S all over the world are held by Indians ,this is quite evident of the fact that Indians have the potential to run the corportate conglomerates , but despite of such vast potential and presence India is home to odd two or three such companies. The modi government has been successful in identifying this underlying problem and start up India is the answer to it. OLA, PAYTM, ZOMATO, OYO etc are all start ups that have revolutionised Indian markets by giving all of us a new perspective to look at consumer based industry, if we look 10 years down the line we don't even realise when did these start ups gain eminence and became an indispensable part of our day to day life.. Start ups are fuelling innovation at a rapid rate and are breaking the conventional norms of business,they themselves are acting as financers for upcoming start ups as for established start ups this is the same road which they took few years back , in time to come this whole start up mechanism would become a self sustained chain boosting multi-fold growth in all sectors. Start up India ultimately aims towards highlighting the importance of accelerating growth in the infrastructure sector by leveraging home grown technologies and solutions

In today's dynamic world where globalisation is reaching new heights , India's presence on the world map is largely dependent on its contribution to the digital sector, start ups are majorly digitally based enterprises therefore their growth is very imperative in terms of India's footprint on the world digital forum. While Make In India was devised to transform India into a global design and manufacturing hub from an import-centric consumer market, the Digital India programme was about reviving infrastructure projects and bring a measure of digitisation in every aspect of life — from finance to education to commerce and governance. Together, Digital India and Make In India served as a powerful call to action for Indian innovators, citizens and business leaders. The economy is propped by digital products and services, which is where startups have emerged as the biggest advocate of Digital India. Key sectors such as education, banking & finance, B2B trade and commerce, governance and delivery of essential services, agriculture and others have been transformed by a mix of startup innovation backed by policy push. With the proliferation of digital infrastructure , Indian start ups have the capability and opportunity to reach global markets and establish themselves by incorporating global standards

AUTHOR: YASHOVARMAN SINGH

“Underprivileged” Youth

The empowerment of the weaker section sections of the population has remained a project of utmost significance for the Government since independence. Policy makers have delved upon number of plans and programmes that caters to the needs of the members from the less privileged. Emphasis has been given in enhancing the skills and capabilities for ensuring rapid economic development and assists them with opportunities to integrate in the national mainstream. While the initial optimism did play a critical role in encouraging inclusion of members of dalit communities into different institutional framework in the country, the inefficient administrative workspaces and lack of enthusiasm in the political arena has pushed the initiatives into a dormant state. However, one can witnessed a new revival in the formulation and implementation of plan and programmes concerning the dalits in India with the coming of the Modi government. Prime Minister Narendra Modi and his government have been persistently working in constructing an inclusive language that cuts across all castes and communities. In the last few years, many schemes related to the educational and economic sector has been formulated by the government and earlier ones were revived in order to promote holistic growth within the community. Following are few schemes that has been able to provide major incentives to the members of the SC community and allowed them with an opportunity to secure a dignified life.

POST MATRIC SCHOLARSHIP

The Modi government decided to revive the Post Matric Scholarship to students belonging to Scheduled Castes (PMS-SC) scheme, which is expected to benefit over 4 crore SC students in the next five years. The objective of the scheme is to increase the Gross Enrolment ratio of SC students in higher education and to provide them with assistance to complete their education. The Cabinet has approved a total investment of Rs 59,534 crore and change in the fund-sharing formula eliminating any intermediate channel and

money being directly depositing in the accounts at the same time increase the percentage of the students receiving the benefits.

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP TO THE SC STUDENTS STUDYING IN CLASSES IX AND X

It is a centrally sponsored scheme implemented through the state governments and union territories. The scheme is primarily been launched to lower the number of school dropouts, to improve their participation and help the parents of SC children for education of their ward. It assists them to transition rather smoothly from the elementary to the secondary education stage. By extending scholarships to SC students whose annual parental income does not exceed Rs 2.5 lakhs the scheme has the potential to rejuvenate the SC participation in secondary education. For the year 2020-21, a total of Rs 11,88,31,75,301 has been disbursed.

CENTRAL SECTOR SCHOLARSHIP SCHEME OF TOP CLASS EDUCATION FOR SC STUDENTS

The scholarship is aimed at promoting qualitative education among SC students by providing them full financial support to them beyond class XII. The scheme aims to meet the requirements for tuition fees, living expenses, books and a computer. The selection criterion is completely merit based and the annual income ceiling for disbursement of the scholarship should not exceed Rs 4.5 lakh.

NATIONAL OVERSEAS SCHOLARSHIP

The scheme facilitate the low income students belonging to the Scheduled Castes, Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, Landless Agricultural Labourers and Traditional Artisans category to obtain higher education viz., Master degree or Ph. D courses by studying abroad thereby improving their Economic and Social status. The Scheme provides financial assistance to the selected candidates for pursuing Masters level courses and Ph.D. courses abroad in the Institutions/Universities accredited by the Government/an authorized body of that country in any fields of study. 30% of the awards for each year are earmarked for women candidates.

NATIONAL FELLOWSHIP FOR PROVIDING FELLOWSHIP TO SCHEDULE CASTE STUDENTS

The scheme was introduced to provide incentives to students belonging to the SC community to pursue their higher studies (M.Phil/Ph.D) in Science, Humanities, Social Science and Engineering and technology in Universities recognised by the University Grant Commission. The academic spaces are often being criticised of its exclusive nature, the introduction of 2000 new Fellowships per year to Scheduled Castes students provide them with an opportunity to enter the field of research and contribute their understanding.

FREE COACHING SCHEME FOR SC AND OBC STUDENTS

The purpose of the scheme is to provide quality coaching classes for economically disadvantaged SC and OBC candidates so that they will be able to appear in competitive examinations and succeed in obtaining an appropriate job. Under the scheme students belonging to SCs and OBCs having total family income from all sources of Rs.8.00 lakh or less per annum will be eligible for benefits.

PRADHAN MANTRI ADARSH GRAM YOJANA

The objective of this Scheme is to ensure integrated development of the selected villages with more than 50% SC population. The aim is to build a village infrastructure wherein people have access to all the basic facilities that are crucial for a dignified living enabling everyone to utilise their potential to the maximum. Different indicators are identified to monitor the growth and living standards of the community. The particulars of the 50 indicators were listed under 10 domains namely drinking water and sanitation, education, health and nutrition, social security, rural roads and housing, electricity and clean fuel, agricultural practices, financial inclusion, digitisation and livelihood and skill development. The Government of India is planning to cover all the eligible 26968 villages by the end of 2014-25. From 2014 to 2021 a total expenditure of Rs 1630.85 crore has been spent on the project

STAND UP INDIA

The scheme facilitates bank loans between 10 lakh and 1 crore to at least one SC/ST borrower and at least one woman borrower per bank for setting up a greenfield enterprise. The number of applications sanctioned has grown 27.3 per cent from 91,319 sanctioned as of March 10, 2020, up from 55,342 applications as of March 7, 2018. The margin money requirement for Standup India loans was reduced from up to 25 per cent to up to 15 per cent allowing for greater inclusion and accessibility of the scheme. The scheme will play a critical role in revolutionising the MSME sector allowing people from the marginalised to take part concomitantly. The scheme has onboarded 24,699 handholding agencies and 348 lenders connecting over 1.51 lakh bank branches.

CREDIT ENHANCEMENT GUARANTEE SCHEME FOR THE SCHEDULED CASTES (SCS)

This scheme is to promote entrepreneurs among the Scheduled Castes in India oriented towards innovative growth technologies. It is a social section initiative to be implemented nationally. Financial assistance to the entrepreneurs among the Scheduled Caste is to be offered by the way of Credit Enhancement Guarantee to Banks and Financial Institutions, under this scheme. These entrepreneurs are expected to create

wealth, value, jobs (direct and indirect) along with contributing to confidence-building and in giving impetus to profitable businesses. Asset creation that is a part of this scheme would have forward and backward linkages which will further chain effect at the local and societal level to strengthen SC communities.

NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NSKFDC)

Set up on 24th January 1997 under the Ministry of Social Justice & Empowerment , wholly owned by the Govt. of India as a Company "Not for Profit" under Section 25 of the Companies Act, 1956. This Apex Corporation aims at overall socio-economic development of Safai Karamcharis, Scavengers and their dependents throughout India. State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by State Govts/UT Administrations, Regional Rural Banks (RRBs) and Nationalised Banks, are primarily responsible for implementing schemes or programmes under this scheme. The SCAs/RRBs/Nationalised Banks are provided financial assistance at concessional rates of interest for onward disbursement to the target group of NSKFDC.

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NFSDC)

The primary goal is financing income generating activities of SC beneficiaries living below Double the Poverty Line Limits (presently Annual Family Income Rs.98000/- for Rural Areas and Rs.1,20,000/- for Urban Areas), this scheme assist the target group by way of loans, Skill Training, Entrepreneurship Development Programmes and Providing Marketing Support through State Channelizing Agencies (SCAs), RRBs, Public Sector Bank and Other Institutions. As on 31 August 2021 a total of Rs 5272.67 lakh has been disbursed.

SELF -EMPLOYMENT SCHEME FOR REHABILITATION OF MANUAL SCAVENGERS (SRMS)

With the aim to rehabilitate the remaining manual scavengers and their dependents in alternative occupations by March 2009, this scheme was introduced in January 2007. As the target could not be met there was an extension of this scheme up to March 2010. The provision added to the extended scheme was that there would be provision for the coverage of spill-over of beneficiaries even thereafter, if needed. According to the revised scheme, one manual scavenger from each family, who are identified under the scheme, are provided one-time cast assistance. The identified manual scavengers and their dependents are offered project based back-ended capital subsidy up to Rs. 3,25,000 and concessional loan for undertaking self-employment ventures. Skill development training for duration of up to two years is also provided to the beneficiaries. During this term, a stipend of Rs. 3000 per month is also given to them.

SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE TO SCHEDULED CASTE SUB PLAN (SCA TO SCSP)

The plan was introduced in the 6th Plan to channelize the flow of outlays and benefits from different sectors of development in the Annual Plans of States/UTs and Central Ministries. The target population of the plan are the Scheduled Castes people living below the poverty line. By providing resources for filling the critical gaps the aim of the plan is to provide an impetus to family oriented schemes of economic development of SCs below the poverty line. 15% of the total SCA released to the States/UTs can be utilized by them exclusively on viable income generating economic development schemes/Programmes for SC Women. In 2014, Rs 105100 lakh has notational been allotted of which Rs 79024.50 has been actually released.

SCHEME OF ASSISTANCE TO SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT COORPORATION (SCDCS)

The scheme provide assistance to finance the employment oriented schemes covering diverse areas of economic activities which inter-alia include (i) agriculture and allied activities including minor irrigation (ii) small scale industry (iii) transport and (iv) trade and service sector. The primary function of the scheme is to identify the eligible SC families and encourage them to undertake economic development schemes sponsoring the schemes to financial institutions for credit support, providing financial assistance in the form of the margin money at a low rate of interest, providing subsidy out of the funds made available to the States under the Scheme of Special Central Assistance to Special Component Plan of the States to reduce the repayment liability and providing necessary tie up with other poverty alleviation programmes.

VENTURE CAPITAL FUND FOR SCHEDULED CASTES

It is a social sector initiative to promote entrepreneurship among the SC population in India to create wealth and value for society as well as promote profitable businesses. Special preferences will be given to SC women entrepreneurs while considering under the scheme. The scheme was launched with an initial capital of Rs 200 crore and under the scheme financial assistance upto Rs 15 crore for a period of six years would be provided to the SC entrepreneurs. It has helped in enhancing direct and indirect employment generation for SC population creating a chain effect that ensures their participation and inclusion at the country level. Under the scheme as of now 89 companies have availed disbursement, 120 companies has received sanctioned assistance, a total of Rs 450.19 crore has been sanctioned of which Rs 278.77 crore has been disbursed.

मुस्लिम समाज में जातिवाद और सामाजिक न्याय का सवाल

जब भी भारतीय मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार का प्रश्न आता है तो अक्सर बुद्धिजीवी लोगो द्वारा यह उनका अंतरिक मामला बता कर पल्ला झाड़ने की कोशिश किया जाता रहा है। विशेष रूप से जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो जहां एक ओर हिन्दू समाज के सामाजिक न्याय की चर्चा तो खूब होती है लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय पर या तो मौन धारण कर लिया जाता है या मुस्लिम समाज को एकरूप बता कर पूरे बहस पर विराम चिन्ह लगा दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम समाज एक इकाई है ?

मुस्लिम समाज स्पष्ट रूप से विदेशी अशराफ(शासक वर्गीय उच्च वर्ग) और देशज पसमांदा(मुस्लिम धर्मावलंबी आदिवासी, दलित और पिछड़े) समाज में विभक्त है। यही नहीं पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में नस्लवाद, जातिवाद, ऊंच-नीच किसी ना किसी रूप में खुलेआम पाया जाता है तुर्की में काली पगड़ी सिर्फ सैयद ही धारण कर सकता है भारत के कश्मीर प्रांत में भी ऐसा देखा जाता है। यमन के अखदाम जो स्वच्छकार होते हैं उनके साथ छुआ छूत आम तौर से पाया जाता है। इस्लाम के आधिकारिक श्रोतों हदीस और इस्लामी फीक्ह (विधि) में खलीफा के चयन और लेकर शादी विवाह तक में नस्ल, जाति और क्षेत्र (अरबी/अजमी) आधारित भेदभाव स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रकाशित "मजमूये कवानीने इस्लामी" जिसे बोर्ड ने मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के मामले में एक वैधानिक दस्तावेज की मान्यता दे रखा है, उक्त बातों को समर्थन करता है। इस्लाम में जातिवाद है कि नहीं यह ज्ञानात्मक बहस का मुद्दा तो हो सकता है लेकिन मौजूदा समय में जो इस्लाम प्रचलित है वह पूरी तरह से जातिवादी के रंग से ओत प्रोत है।

भारत में अरबी, ईरानी और मध्य एशिया के मुस्लिमो के आगमन के साथ ही इस्लामी स्टाइल के नस्लवाद और जातिवाद का भी पदार्पण होता है। जो उनके शासन काल(जिसे अशराफ़ शासन काल भी कह सकते हैं) में साफ तौर से दृष्टिगोचर होता है। नस्ल और जाति के बड़प्पन का एहसास और उसकी संस्थापन इस तरह का था कि बाजाब्ता एक "निकाबत" नामक विभाग था जो शासन प्रशासन में नियुक्ति के लिए जाति एवं नस्ल की जांच करता था और पहले से नियुक्ति हुए संदिग्ध लोगो की भी जांच करता था। अल्तमश के शासनकाल में ऐसे 33 लोगो को शासन प्रशासन से बर्खास्त करने का प्रमाण मिलता है जिनका सम्बन्ध तथाकथित नीच जाति(हिन्दू और मुसलमान दोनों) से था।

काका कालेलकर समिति से लेकर मण्डल आयोग और सच्चर कमिटी तक में मुस्लिम समाज के जातिगत विभेद पर खुल कर चर्चा किया गया है। मण्डल आयोग द्वारा तो मुस्लिम पिछड़ी जातियों को आरक्षण के कैटेगरी में शामिल कर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवम् क्रांतिकारी कदम भी बढ़ाया गया था।

बात साफ हो जाती है कि ना सिर्फ सामाजिक बल्कि धार्मिक आधार पर भी मुस्लिम समाज जातियों एवम् जनजातियों में बटा हुआ है जहां बन गुजर, भील, सेपिया, बकरवाल जैसे आदिवासी, मेहतर, नट, धोबी, हलालखोर जैसी दलित और धुनकर, डफाली, तेली, बुनकर जैसी पिछड़ी जातियां स्पष्ट रूप से पायी जाती हैं।

ऐसा देखने में आता है कि प्रायः लगभग सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक नाम पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व की ही मांग होती रही है जिसका पूरा लाभ पहले से ही मुख्य धारा में स्थान प्राप्त साधन संपन्न अशराफ वर्ग ही मुस्लिम नाम पर उठाता आ रहा है, वहीं मुस्लिम समाज के आदिवासी और पिछड़ा समाज जो देशज पसमांदा कहलाता है, जिसकी संख्या कुल मुस्लिम जनसंख्या का 90% है आजादी के 74 वर्षो बाद भी वंचित समाज बना हुआ है।

पूर्व सांसद अशफाक हुसैन अंसारी ने अपनी किताब "बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ओबीसी एंड दलित मुस्लिम" में प्रथम से लेकर चौदहवीं लोकसभा तक के सांसदों का ब्योरा देते हुए लिखते हैं कि अब तक चुने गए कुल मुस्लिम सांसदों की संख्या 400 है, इन में 340 अशराफ वर्ग और पसमांदा समाज से केवल 60 सांसद ही चुने जा सके हैं, उपर्युक्त डेटा से यह साफ पता चलता है कि मुस्लिम उच्च वर्ग यानि अशराफ अपनी आबादी के दुगुने से भी अधिक प्रतिनिधित्व हासिल किए हुए है वही पसमांदा की भागेदारी चिंतनीय है। यह तो सिर्फ लोक सभा का डाटा है, विधान सभाओं और नगर पालिकाओ एवम् पंचायतो में स्तिथि कमोबेश यही है। विधायिका की तरह न्यायपालिका एवम् कार्यपालिका में पसमांदा समाज का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के आधार पर न्यूनतम है। जबकि अशराफ समाज की भागेदारी सभी क्षेत्रों में लगभग दुगनी है। अल्पसंख्यक और मुस्लिम नाम से संबंधित प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों में भी लगभग यही स्थिति है। यहां एक बात यह भी बड़ी अजीब है कि स्वयं मुस्लिमों द्वारा संचालित संस्थाओं में भी जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते इस्लामी, जमीयतुल उलेमा, मिल्ली काउंसिल, मजलिसे मशावरत, वक़्फ़ बोर्ड, बड़े स्तर के मदरसे, इमारते शरिया आदि जो पुरे मुस्लिम समाज के नुमाइंदगी का दावा

करती हैं स्थिति इससे भिन्न नहीं है यहां भी सिर्फ चंद विशेष अशराफ परिवारों के ही लोग देखने को मिलते हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण रहा है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले विभिन्न पसमांदा आंदोलन पहले मुस्लिमो द्वारा संचालित संस्थानों में भागेदारी को लेकर अधिक मुखर रहें हैं।

किसी भी देश के सम्पूर्ण विकास के लिए उस देश में बसने वाले सभी समाजों का प्रत्येक क्षेत्र में प्रयाप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, देशज पसमांदा समाज जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 12 से 13 प्रतिशत है और जिसकी सभी क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर पर भागेदारी एक चिंता का विषय है।

मीडिया को, सरकार को, विपक्ष को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये सोचने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि मुस्लिम समाज भी ऊंच नीच, पिछड़ा और दलित वर्ग में बटा है और इनके अंदर यह भेद हिन्दू समाज से भी ज्यादा गहराई से बैठा हुआ है। अतः सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात नही बल्कि उसके अंदर मौजूद दबा कुचला पसमांदा के भागेदारी की बात मुखर होकर करने से ही हम एक नए भारत को निर्माण कर सकते हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और मुस्लिम समाज को एक समरूप समाज मानकर अब तक बनती आ रही नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

फैयाज अहमद फैजी

(लेखक, अनुवादक, स्तंभकार, मीडिया पैनलिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पेशे से चिकित्सक हैं)

भारतीय पदक विजेता, टोक्यो 2021

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए. भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया है. अब तक ओलंपिक खेलों में यह भारतीय खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए देश को इस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया. उनसे पहले पहलवान बजरंग पूनिया ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतकर देश के पदकों की संख्या बढ़ाई. आइए जानते हैं इस ओलंपिक में किन भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.

नीरज चोपड़ा (गोल्ड मेडल)

नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस जिले पानीपत में हुआ है, जो अपनी तीन लड़ाईयों के लिए मशहूर है। यहां के एक छोटे से गांव खांद्रा में किसान के घर पर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी।

नीरज अपने बचपन में काफी मोटे थे, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे, उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र से दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा, तो इसमें वो भी उतर गए। वहां से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया, वह अब ओलंपिक गोल्ड पर जाकर लगा है।

पढ़ाई के साथ वे जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे, इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए आईएएएफ वर्ल्ड यू-20 चैम्पियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड जीता। जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंड में बतौर जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर के तौर पर नायब सुबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डारेक्ट ऑफिसर बना दिया गया।

आर्मी में जॉब मिलने से खुश नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, मेरे परिवार में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, मैं अपने संयुक्त परिवार का पहला सदस्य हूं जो सरकारी नौकरी करने जा रहा हूं, यह हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ-साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूं।

नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं. नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया. उन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है. साथ ही साथ ये भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल भी है. नीरज की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर सारा भारत गौरवान्वित है.

रवि दहिया (सिल्वर मेडल)

हरियाणा के रहने वाले रवि कुमार दहिया का जन्म 12 दिसंबर 1997 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनका घर सोनीपत जिले के नाहरी गांव में हैं। रवि के पिता का नाम राकेश दहिया है। रवि के पिता के पास खुद की जमीन नहीं थी। उन्होंने खेती करने के लिए खेत को किराए पर लिया था। रवि को पहलवान बनाने के लिए उनके पिता ने काफी परिश्रम किया। वे रवि के लिए हमेशा दूध और फल देने के लिए गांव से 40 किमी दूर स्टेडियम जाया करते थे। आपको बता दें कि रवि ने अपनी पहलवानी की ट्रेनिंग दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में की है।

पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किग्रा भार वर्ग कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने अपनी कामयाबी से भारत के लिए खाते में दूसरा सिल्वर मेडल जोड़ दिया. उनसे देश को गोल्ड की उम्मीदें थीं, लेकिन वे फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाए. उम्मीद करते हैं अगली बार वो अपने मेडल का रंग सुनहरा जरूर कर लेंगे.

पीवी सिंधु (ब्रॉन्ज मेडल)

पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में पीवी रमना (पिता) और पी विजया (मां) के घर हुआ था। उनके माता-पिता राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। सिंधु के पिता 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। उन्हें खेल में उनके योगदान के लिए वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार मिला।

पीवी सिंधु ने अपनी स्कूली शिक्षा औक्सिलियम हाई स्कूल, हैदराबाद और सेंट एन कॉलेज फॉर विमेन, हैदराबाद में की। पुलेला गोपीचंद, 2001 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन बैडमिंटन को अपने करियर के रूप में चुनने के लिए सिंधु की प्रेरणा बनीं।

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. वे ओलंपिक में लगातार दो बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गईं. सिंधु ने सबसे पहले 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं. इस बार उन्होंने उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को हराकर मेडल अपने नाम किया.

लवलीना बोरगोहेन (ब्रॉन्ज मेडल)

13 साल की उम्र में लवलीना और उनकी जुड़वा बहनों (लीचा और लीमा) को किक बॉक्सिंग सीखने के लिए भेजा गया था. दोनों बहनें किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल तक पहुंच गईं. लेकिन उस बीच लवलीना गेम बदलकर बॉक्सिंग रिंग में आ चुकी थीं. लवलीना की मां ममोनी बोर्गोहेन बताती हैं कि अपनी स्कूलिंग के टाइम पर वह हर खेल गतिविधि में हिस्सा लेती थी.

बचपन का एक किस्सा बताते हुए ममोनी बोर्गोहेन ने कहा, 'एक बार लवलीना के पिता उनके लिए मिठाई लाए. मिठाई जिस अखबार में लपेटकर लाई गई थी लवलीना उसे पढ़ने लगीं. तब पहली बार लवलीना ने मोहम्मद अली के बारे में पढ़ा और फिर बॉक्सिंग में उनकी रुचि बढ़ी.'

जब लवलीना 9वीं क्लास में थीं तब ही भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के एक कोच की नजर उनपर पड़ी थी. तब से वह बॉक्सिंग में लगातार आगे ही बढ़ती गईं. वह मोहम्मद अली के साथ-साथ माइक टायसन की भी फैन हैं.

बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया. उन्होंने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने देश के खाते में एक ब्रॉन्ज मेडल जोड़कर देश को गर्वित कर दिया.

बजरंग पूनिया (ब्रॉन्ज मेडल)

बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को हरियाणा के झाझर गाँव में हुआ था. बजरंग पूनिया के पिता का नाम बलवान सिंह पुनिया हैं. बजरंग पूनिया के पिता बलवान सिंह पुनिया भी पेशेवर पहलवान रह चुके है. बजरंग पूनिया की पत्नी का नाम संगीता फोगाट है. संगीता फोगाट भी पहलवान रह चुकी है. 25 नवंबर को बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट शादी के बंधन में बंधे. संगीता द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट की बेटी हैं.

बजरंग पूनिया ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गाँव से ही पूरी की है. इसके बाद बजरंग पूनिया ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा हासिल की है. बजरंग पूनिया ने भारतीय रेलवे में टिकट चेकर (TTE) का भी काम किया है.

बजरंग पूनिया को कुश्ती विरासत में मिली है. उन्होंने महज 7 साल की उम्र में कुश्ती करना शुरू कर दिया था. बजरंग पूनिया के पिता भी पहलवान थे तो उन्होंने अपने बेटे के सपने को पूरा करने में बहुत सहयोग किया. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बलवान सिंह पुनिया ने अपने बेटे को पहलवान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. बजरंग पूनिया ने 14 साल की उम्र में अखाड़े में ट्रेनिंग करना शुरू की. इसके बाद उनकी मुलाकात ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त से हुई. योगेश्वर दत्त ने बजरंग पूनिया को कुश्ती के दाव पेच सिखाए.

पहलवान बजरंग पूनिया ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में शानदार सफलता हासिल करते हुए फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किग्रा भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया. बजरंग ने भारत की झोली में चौथा कांस्य और कुल छठां पदक डाला. बजरंग ने इस मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाबेकोव को हराकर पदक जीता.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम (ब्रॉन्ज मेडल)

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है. इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था. टीम ने इस ओलंपिक में अद्‌भुत प्रदर्शन किया. हॉकी टीम के सभी प्लेयर्स से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर उन्हें देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी. हॉकी के स्वर्णिम इतिहास को दुबारा जीवंत बनाकर हॉकी टीम ने हरेक भारतीय को गर्व करने का अवसर दिया है.

मीराबाई चानू (सिल्वर मेडल)

मीराबाई चनू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोंगपेक काकचिंग गांव में हुआ था. शुरुआत में मीराबाई का सपना तीरंदाज बनने का था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने वेटलिफ्टिंग को अपना करियर चुनना पड़ा. मणिपुर से आने वालीं मीराबाई चनू का जीवन संघर्ष से भरा रहा है. मीराबाई का बचपन पहाड़ से जलावन की लकड़ियां बीनते बीता. वह बचपन से ही भारी वजन उठाने की मास्टर रही हैं.

मीराबाई बचपन में तीरंदाज यानी आर्चर बनना चाहती थीं. लेकिन कक्षा आठ तक आते-आते उनका लक्ष्य बदल गया. दरअसल कक्षा आठ की किताब में मशहूर वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी का जिक्र था.

इम्फाल की ही रहने वाली कुंजरानी भारतीय वेटलिफ्टिंग इतिहास की सबसे डेकोरेटेड महिला हैं. कोई भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर कुंजरानी से ज्यादा मेडल नहीं जीत पाई है. बस, कक्षा आठ में तय हो गया कि अब तो वजन ही उठाना है. इसके साथ ही शुरू हुआ मीराबाई का करियर.

भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का खाता खोला. चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में यह कामयाबी हासिल की. उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो और स्नैच में 87 किलो से कुल 202 किलो वजन उठाकर पदक अपने नाम किया.

टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी

भाविना पटेल

एक छोटी परचून की दुकान चलाने वाले हंसमुखभाई पटेल की बेटी भाविना को पदक का दावेदार भी नहीं माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से इतिहास रच दिया.

भाविना पटेल का पूरा नाम भाविना हसमुख पटेल है ये मूल रूप से गुजरात के रहने वाली हैं इनका जन्म 06 नवम्बर 1986 को गुजरात के मेहसाणा जिले के सुधियां गांव में हुआ था। वर्ष 2004 में जब 18 वर्ष की थीं तो भाविना अपने गृहनगर से अहमदाबाद चलीं गई और फिलहाल अपने परिवार के साथ वहीं रहती हैं। इनकी शादी निकुल पटेल से हुई है जो की एक विजनेस मैन हैं इनके दो पुत्र हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भाविनाबेन पटेल ने दिलाया था. टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भाविना रजत पदक जीतने में सफल रही थीं. 34 साल की भाविना ने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की

बोरिस्लावा रांकोविच को हराकर पदक पक्का कर लिया था. इसके बाद भाविना ने सेमीफाइनल में चीन की ही झांग मियाओ को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी. हालांकि भाविना को फाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर-1 झाउ यिंग ने हरा दिया, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

निषाद कुमार

दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। ऐसे ही एक शख्स हैं उपमंडल अम्ब की कटौहड कलां पंचायत के बदायूं गांव के दिव्यांग निषाद कुमार।

एक साधारण परिवार में मुश्किलों के बीच पले बढ़े हैं. निषाद का पैरालंपिक तक का सफ़र मुश्किलों भरा रहा है. बचपन में मां जब पशुओं के लिए घास काट रही तो निषाद का हाथ उसमें चला गया और कट गया.

यहीं से निषाद की ज़िंदगी बदल गई व ऊंचे कूद का सफ़र शुरू हुआ क्योंकि निषाद की मां भी स्पोर्ट्स में रही थी इसलिए बेटे को प्रोत्साहित किया. मुश्किल ये थी को निषाद को प्रशिक्षण के लिए कहां भेजा जाए तो मां बाप ने 2500 रुपया देकर हरियाणा भेजा। हरियाणा आने के बाद से निषाद ने अपने हुनर को तराशा और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

निषाद कुमार ने पुरुषों के टी-47 हाई जंप के मुकाबले में भारत के लिए टोक्यो पैरालम्पिक 2021 में रजत पदक जीता है. निषाद कुमार ने पहली कोशिश में 2.02 और दूसरे प्रयास में 2.06 मीटर की जंप लगाई. अमेरिका के डलास वाइज भी इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि वाइज ने भी 2.06 मीटर की जंप लगाई थी. इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका के ही रोडरिक टाउनसेंड ने 2.15 मीटर की कूद के विश्व रिकॉर्ड के साथ हासिल किया.

अवनि लखेरा

अवनी लखेरा का जन्म राजस्थान के जयपुर में 8 जनवरी 2001 को हुआ था इनके पिता का नाम प्रवीन लखेरा और माता का नाम स्वेता लखेरा है। अवनी लखेरा बचपन में शारीरिक रूप से नॉर्मल लड़की थी लेकिन एक घटना के बाद इनके जीवन ही बदल गया। बताया जाता है की अवनी जब ग्यारह वर्ष की थी तब अपने पिता के साथ कहीं जा रहीं थीं उसी क्रम में एक दुर्घटना घटित हो गई और अवनी बुरी तरह से घायल हो गईं इनके पिता की भी पैर टूट गई लेकिन अवनी को ज्यादा ही चोट लगी थी। इलाज के दौरान पता चला की अवनी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो अब शायद ही सही तरीके से चल पाएगी इनके जीवन में अब निराशा के बादल छाए हुए दिखाई दे रहा था तब इनके माता पिता ने अपनी बेटी के अंदर आत्मविश्वास भरना शुरू किया और अंततः अवनी ने यह निर्णय लिया की अब निशानेबाजी में अपना कैरियर बनानी है और फिर इन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया और नतीजा ये है की आज पूरा देश इनपर गर्व कर रहा है। अवनी लखेरा जब शरीर से असमर्थ हो गईं और फिर निर्णय लिया की निशाने बाजी में अपना कैरियर बनाना है तब इन्होंने अभिनव बिंद्रा जी को आदर्श मानकर अपना अभ्यास शुरू किया और घर के नजदीक ही शूटिंग रेंज पर जाकर रोज निरंतर अभ्यास शुरू कर दिया। शूटिंग रेंज पर हीं निशाने बाजी के कोच चंदन सिंह से मुलाकात हुई उन्होंने ने भी अवनी को यह विश्वास दिलाया कि अगर तुम निरंतर सही दिशा में अभ्यास करती हो तो एक दिन जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जायोगी।

बीच बीच में अवनी का निशाना सही नहीं होता और अवनी निराश हो जाती तो कोच चंदन सिंह द्वारा प्रोत्साहित किया जाता की तुम ऐसे हार नहीं मानो और नतीजा आज यह हुआ की अपना नाम पूरे विश्व के पटल पर सुर्खियां में ला दिया।

टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनि लखेरा ने हासिल किया. उन्होंने महिलाओं की आर-2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 में यह सुनहरी सफलता हासिल की. इसके साथ ही अवनि पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं. 19 साल की इस शूटर ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की. इस स्पर्धा का रजत पदक चीन की झांग कुइपिंग ने हासिल किया. वहीं, यूक्रेन की इरियाना शेतनिक को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.

इसके बाद अवनि लखेरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन SH1 स्पर्धा का भी कांस्य पदक जीता. अवनि फाइनल में 445.9 का स्कोर कर तीसरे स्थान पर रहीं. इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन की झांग क्यूपिंग (457.9) और रजत पदक जर्मनी की हिलट्रॉप नताशा (457.1) ने जीता. इसके साथ ही अवनि लखेरा दो पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं.

हरियाणा के बहादुरगढ़ से आने वाले योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो 56 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था. उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर पदक पर कब्जा कर लिया. ब्राजील के बतिस्ता डॉस सैंटोस क्लॉडनी (45.25) ने इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता था. वहीं क्यूबा के डियाज अल्दाना लियोनार्डो (43.36) तीसरे स्थान पर रहे. योगेश कठुनिया की मां मीना देवी ने कहा, 'सिल्वर मेडल ही मेरे लिए गोल्ड मेडल है। देश के लिए गोल्ड मेडल लाना बड़ी बात है। तीन साल तक वह व्हीलचेयर में रहा। मेहनत के लिए वह कभी पीछे नहीं हटता है।'

योगेश कथुनिया

सुमित अंतिल

हरियाणा की मिट्टी ऐसे लाल बड़ा करती है जो खेलों में देश का नाम रोशन करते हैं। सुमित अंतिल भी उन्हीं मे से एक हैं। किसी वक्त कुश्ती में देश को मेडल दिलाने का सपना देखने वाले सोनीपत के इस लाल ने पैरालिंपिक में गोल्डन भाला फेंका। 7 जून 1998 को पैदा होने वाले सुमित का यह सफर कठिनाइयों भरा रहा। छह साल पहले हुए सड़क हादसे में एक पैर गंवा दिया। बावजूद इसके उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। सुमित जब सात साल के थे, तब एयरफोर्स में तैनात पिता की मौत हो गई। तीन बेटियों और इकलौते बेटे को पालना मां के लिए आसान नहीं था। 2015 की एक शाम 17 साल के सुमित की बाइक को किसी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में हमेशा-हमेशा के लिए एक पैर गंवाना पड़ा। कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद साल 2016 में सुमित को नकली पैर लगाया गया। खेलों के प्रति तो शुरू से ही रुझान था। साई कोच वीरेंद्र धनखड़ ने उनका मार्गदर्शन किया। दिल्ली में कोच नवल सिंह ने उन्हें जैवलिन थ्रो के गुर सिखाए। साल 2018 में एशियन चैंपियनशिप में 5वीं रैंक मिली। अगले साल 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता फिर इसी साल हुए नेशनल गेम्स में गोल्ड जीतकर अपनी परेशानियों को उपबल्धियों के आगे बौना साबित कर दिया। जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल (एफ 64 वर्ग) ने भारत को इस पैरालंपिक खेलों का दूसरा स्वर्ण दिलाया था. सुमित ने रिकॉर्ड 68.55 मीटर जैवलिन फेंककर पीला तमगा अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलिया के मिचाल बुरियन (66.29 मीटर) और श्रीलंका के डुलान कोडिथुवाक्कू (65.61 मीटर) ने क्रमश: रजत और कांस्य पदक जीते.

दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. देवेंद्र ने जैवलिन थ्रो (F46 वर्ग) में 64.35 का बेस्ट थ्रो कर रजत पदक हासिल किया. इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक श्रीलंका के दिनेश प्रियान हेराथ के नाम रहा, जिन्होंने 67.79 मीटर का थ्रो किया. श्रीलंकाई एथलीट ने अपने इस प्रयास से देवेंद्र झाझरिया का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.

देवेंद्र झाझरिया का जन्म 10 जून 1981 ई० राजस्थान के चुरू जिले में एक जाट परिवार में हुआ था जब ये करीब 10 वर्ष के थे तो एक दिन दोस्तों के साथ खेलते हुए एक पेड़ पर चढ़ गए वहां बिजली की तार को पकड़ लिया जिससे उनकी बाईं हाथ पूरी तरह जल गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने क्षतिग्रस्त हाथ को काटने का निर्णय लिया हुआ और देवेंद्र को ठीक रहने के लिए ये करना जरूरी भी था। जब स्कूल जाने लगे तो सभी लोग इन्हें यही बोलते थे की जब तक पूरी शरीर ठीक न हो वो क्या कर सकता है इससे कुछ नहीं होगा इनके मन को भी कभी कभी ऐसा लगता था लोग ठीक कह रहे हैं तभी इनके स्कूल में खेल का एक आयोजन हुआ उसमें बहुत से शिक्षक और छात्र भाग लिए उसमें एक शिक्षक आए थे उनका नाम था आर डी शर्मा जो बच्चों को जैवलिन थ्रो की कोचिंग देते थे। उन्होंने देवेंद्र की प्रतिभा की पहचान की और इनके मनोबल को बढ़ाया। इसके बाद देवेंद्र ने अपने गुरु श्री आर डी शर्मा जी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया और आज तक चलते रहे। आर डी शर्मा जी को द्रोणाचार्ज पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. जब पहली बार देवेन्द्र ने 2004 के एथेंस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत तो इस जीत का श्रेय अपने गुरु श्री आर डी शर्मा जी को दिया। उनका ये शानदार सफर अभी तक जारी है। उम्मीद है देवेंद्र आगे भी देश को गौरवान्वित करते रहेंगे।

देवेंद्र झाझरिया

सुंदर सिंह गुर्जर

जिंदगी कब करवट बदल ले कहा नहीं जा सकता इसलिए इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए. इसका जीता जागता उदाहरण हैं टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर. एक वक्त ऐसा भी था जब सुंदर आत्महत्या करने की सोचने लगे थे. इनका जन्म 1 जनवरी 1996 में राजस्थान के करौली में टोडाभीम तहसील के देवलेन गांव में हुआ था. खास बात ये हैं कि वह बचपन से दिव्यांग नहीं थे. वह साल 2015 तक सामान्य खेलों में हिस्सा लेते थे. इसी साल एक दोस्त के घर, टीन की चद्दर इनके हाथ पर गिर गई, जिसकी वजह से कलाई को काटना पड़ा. इस हादसे के बाद सुंदर गुर्जर जबर्दस्त निराशा में डूब गए, मगर फिर खुद को संभाला और सिर्फ एक हाथ से ही भाला यानी जैवलिन फेंकना शुरू किया.

जैवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह गुर्जर ने F-46 वर्ग में ही भारत के लिए कांस्य पदक जीता. सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर जैवलिन फेंका, जो इस सत्र में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. सुंदर को जैवलिन के अलावा डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में भी पारंगत हासिल है. 2017 में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक्स ग्रां प्री में सुंदर ने इन तीनों ही स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता था.

सिंहराज

सिंहराज सिंह अधाना हरियाणा के बहादुगढ़ के रहने वाले हैं. उनका परिवार आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा मजबूत नहीं है. ऐसे में सिंहराज के लिए शूटिंग जैसे महंगे खेल का खर्च उठाना आसान नहीं था. सिंहराज ने कुछ समय पहले पीएम मोदी से बातचीत में बताया था कि उनकी पत्नी ने उनके सपने के लिए काफी त्याग किए हैं. सिंहराज सिंह ने कहा, 'पहला नेशनल मेडल जीतने के बाद ही मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे पैरालिंपिक में मेडल जीतना है. सिंहराज अधाना एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. लगभग 35 साल की उम्र में काफी देरी से शूटिंग की शुरुआत की. इसके बावजूद अधाना को अपनी कामयाबी का यकीन था. उन्होंने अपने और पैरालिंपिक मेडल के बीच अपनी उम्र और अपनी कमजोरी को कभी नहीं आने दिया. एसएच1 वर्ग में निशानेबाज एक हाथ से ही पिस्टल थामते हैं. उनके एक हाथ या पांव में विकार होता है. इसमें निशानेबाज नियमों के अनुसार बैठकर या खड़े होकर निशाना लगाते हैं.

शूटर सिंहराज ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था. हरियाणा के रहने वाले सिंहराज ने फाइनल में 216.8 का स्कोर कर यह उपलब्धि हासिल की. चीनी खिलाड़ियों यांग चाओ (237.9) और हुआंग जिंग (237.5) ने क्रमशः गोल्ड और सिल्वर जीता.

39 साल के सिंहराज ने इसके बाद P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल एसएच-1 फाइनल में भी रजत पदक हासिल किया. फाइनल में सिंहराज ने 216.7 का शानदार स्कोर किया. इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक भारत के ही मनीष नरवाल (218.2) ने हासिल किया. वहीं रूसी पैरालंपिक समिति (RPC) के सर्गेई मालिशेव (196.8) ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रहे.

मरियप्पन थंगावेलु

मरियप्पन थंगावेलु का जन्म 28 जून 1995 को तमिलनाडु के गांव पेरियावादगमपट्टी, सालेम में हुआ था। उनके घर में एक बड़ी बहन और दो छोटे भाई है। उनके पिता का एक हादसे में निधन हो गया था। मरियप्पन का बचपन बहुत गरीबी में बीता है। पति की मौत के बाद उनकी मां सरोजा देवी ईट उठाने का काम किया करती थी। लेकिन एक दिन उन्हें सीने में दर्द हुआ तो मरियप्पन ने किसी से 500 रुपये उधार लेकर उनका ईलाज करवाया। जिसके बाद सरोजा देवी ईठ उठाने का काम छोड़कर सब्जियां बेचना शुरू कर दी। जब मरियप्पन 5 साल के थे, उनके साथ वो हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया। दरअसल, जब वह सड़क पर खेल रहे थे, तो एक बस ने उनको इतनी जोर से टक्कर मारी की उनका एक पैर खराब हो गया। इतना ही नहीं पैर खराब हो जाने की वजह से डॉक्टरों को उनका पैर तक काटना पड़ा। मरियप्पन के ईलाज कराने के लिए उनकी मां को 3 लाख रुपये उधार लेने पड़े। इस लोन को मरियप्पन का परिवार 2016 तक भी नहीं चुका पाया था। जब पैरालंपिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ तो उस समय तक इनका पूरा परिवार किराए के मकान में ही रहता है। मरियप्पन के साथ भीषण हादसा हो जाने के बाद उन्हें 17 सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़े। जिसके बाद उनके परिवार को कुल 2 लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त हुआ। इसमें से भी 1 लाख रुपये तो वकीलों को फीस के तौर पर चुकाने पड़ें। बाकि बचे एक लाख को उनकी मां ने बैंक में जमा करा दी ताकि भविष्य में मरियप्पन के काम आ सके। मरियप्पन को बचपन से ही वॉलीबाल खेलने का काफी शौक था एक पैर कटने के बाद भी खेलों के लेकर उनकी लग्न को देखकर उनके एक टीचर ने उन्हें हाई जंप करने की सलह दी। जिसके बाद मरियप्पन ने इसमें ही करियर बनाने का मन बनाया। 14 साल की उन्होंने हाई जंप प्रतियोगिता में भाग लिया। जिसमें वह दूसरे नंबर के खिलाड़ी रहें। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद टी-63 स्पर्धा में भारत के लिए रजत

पदक जीता. था. मरियप्पन ने 1.86 मीटर की जंप लगाकर यह कामयाबी हासिल की. अमेरिका के सैम ग्रेव (1.88 मीटर) की छलांग लगाते हुए इस इवेंट का गोल्ड मेडल हासिल किया. 26 साल के मरियप्पन का पैरालंपिक खेलों में यह लगातार दूसरा पदक है. इससे पहले मरियप्पन ने रियो पैरालंपिक (2016) में ऊंची कूद इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया था.

शरद कुमार मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, अभी वो राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहते हैं। जेएनयू से पढ़ाई भी कर रहे हैं। शरद का एक पैर पोलियो बीमारी के कारण खराब हो गया था। यह जन्म से ही काफी कमजोर है। हालांकि उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी भी अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने दी। उन्होंने अपने हौसले से अपनी खुद के कामयाबी की कहानी लिखी है जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। उन्होंने टोक्यो के पैरालिंपिक 2020 में वो कर दिखाया जो हर किसी का सपना होता है। पुरुषों की ऊंची कूद टी-63 स्पर्धा में ही शरद कुमार ने भी भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया. शरद ने 1.83 मीटर का बेस्ट प्रयास कर यह उपलब्धि हासिल की. एक अन्य भारतीय पैरा एथलीट वरुण सिंह भाटी इस स्पर्धा में सातवें स्थान पर रहे. गौरतलब है कि भाटी ने रियो पैरालंपिक में भी भारत के लिए कांस्य पदक जीता था.

शरद कुमार

प्रवीण कुमार

18 साल के इस होनहार युवक का जन्म उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ था। प्रवीण कुमार के बारे में सबसे दिलचस्प बात ये है कि उनको कुछ वर्षो पहले तक पैरा खेल या ऊंची कूद के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें वॉलीबॉल में रूचि थी लेकिन एक बार उन्होंने ऊंची कूद प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्हें एथलेटिक्स विशेषकर ऊंची कूद से लगाव हो गया।

पुरुषों हाई जंप टी64 वर्ग के फाइनल में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की कूद लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया. इस शानदार प्रदर्शन के दौरान प्रवीण ने नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया. इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम-एडवर्ड्स जोनाथन (2.10 मीटर) ने जीता. वहीं पोलैंड के लेपियाटो मासिएजो (2.04 मीटर) कांस्य पदक जीतने में सफल रहे.

तीरंदाज हरविंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया. तीसरे स्थान के मुकाबले में हरविंदर ने साउथ कोरिया के सू मिन को 6-5 से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही हरविंदर पैरालंपिक के तीरंदाजी इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए.

हरविंदर सिंह

मनीष नरवाल

मनीष नरवाल एक भारतीय पैरा पिस्टल शूटर हैं। जिनका जन्म 17 अक्टूबर 2001 में हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। मनीष बड़े होकर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन जन्मजात एक बीमारी ने उनका ये सपना पूरा नहीं होने दिया। लेकिन कहते है, ना जिस इंसान में कुछ कर गुजरने का इरादा हो, वो अपना मुकाम हासिल कर ही लेता हैं। फुटबॉलर तो नहीं लेकिन मनीष भारत के स्वर्णिम एथलीट जरूर बन गए है। दरअसल, दाहिने हाथ में जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हुए मनीष को फुटबॉल खेलने का काफी शौक था। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन शारीरिक कमी के चलते वह प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन पाए। दिव्यांगता ने उन्होंने कई चुनौतियां दी, मगर ये चुनौतियां मनीष के एथलीट बनने के इरादों को कमजोर नहीं कर पाई। फुटबॉल नहीं खेल पाने के चलते उनके परिवार के एक सदस्य ने उन्हें शूटिंग में जाने की सलाह दी। उन्होंने उनकी बात मानी और पैराशूटर बनने की ठानी।

शूटर मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल एसएच-1 फाइनल में 218.2 का स्कोर कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं, मनीष के हमवतन सिंहराज (216.7) ने रजत और रूसी पैरालंपिक समिति (RPC) के सर्गेई मालिशेव (196.8) ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया. फरीदाबाद के रहने वाले मनीष नरवाल (533) ने क्वालिफिकेशन रांउड में सातवां स्थान हासिल कर फाइनल में जगह बनाई.

प्रमोद भगत

4 जून 1988 को जन्मे प्रमोद का ताल्लुक वैसे तो बिहार से है। मगर वो और उनका परिवार ओडिशा के बरगढ़ जिले के अट्टाबीरा में रहता है। पांच साल की उम्र में पैर में पोलियो होने के बाद वह इलाज के वास्ते ओडिशा चले गए थे। पोलियो होने के बाद भी प्रमोद का बैडमिंटन के प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ। टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद प्रमोद ने न सिर्फ देश और ओडिशा बल्कि बिहार का भी मान बढ़ाया है। बैडमिंटन के प्रति उनका जुनून इस कदर था कि वो कई घंटे तक अभ्यास करते थे। शुरुआती समय में उन्होंने जिला स्तर पर कई टूर्नामेंट जीते। फिर पैरा-बैडमिंटन की ओर रुख किया। इसके बाद प्रमोद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।
2018 पैरा एशियाई खेलों में उन्होंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। विश्व चैंपियनशिप में वो चार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कुल मिलाकर प्रमोद ने अब 45 अंतरराष्ट्रीय पदक अपने नाम किए हैं।

प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं. वर्ल्ड नंबर-1 प्रमोद ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स एसएल3 फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर-2 डेनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हराया. गौरतलब है कि प्रमोद भगत ने ग्रुप-ए में अपने दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. फिर सेमीफाइनल मुकाबले में प्रमोद ने जापान के डाइसुके फुजिहारा को 21-11, 21-16 से पटखनी दी.

मनोज सरकार

मनोज का जन्म जनवरी 1990 में रुद्रपुर में हुआ. बचपन में ही दाएं पैर के पंजे के शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद अपने आसपास के बच्चों को बैडमिंटन खेलता देखकर मनोज ने भी इसे खेलना शुरू किया. मनोज के पिताजी दैनिक मजदूर थे और माताजी घर पर ही बीड़ी बनाने का काम करती थीं. ऐसी कमजोर आर्थिक स्थिति में बैडमिंटन के पुराना रैकेट खरीदकर मनोज ने अपनी मेहनत के बल पर खेल में निपुणता हासिल करने की शुरुआती कोशिश की. अपने विषम शारीरिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बैडमिंटन जैसे तेज खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मुक़ाम हासिल किया वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है.

एसएल3 वर्ग में ही मनोज सरकार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता. उत्तराखंड के रहने वाले मनोज ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जापान के डाइसुके फुजिहारा को 22-20, 21-13 से शिकस्त दी थी. इससे पहले मनोज सरकार को सेमीफाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल ने हरा दिया.

सुहास यथिराज

साल 2020 में जब यूपी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर नोएडा कोरोना की मार से बुरी तरह टूट रहा था, लोग महामारी से दम तोड़ रहे थे, अस्पतालों और सरकारी व्यवस्थाएं इस महामारी के सामने घुटने टेक रही थी तो उम्मीद की किरण बनकर एक युवा IAS अधिकारी ने कमान संभाली। 38 साल के इस युवा जिलाधिकारी ने कुर्सी पर बैठते ही अपनी जिम्मेदारियों को इस कदर निभाया कि केंद्र सरकार ने भी कोरोना मैंनेजमेंट के लिए उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। देश के तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में गिने जाने वाले सुहास एलवाई का सफर आसान नहीं था। दाहिने पैर से विकलांग सुहास ने कभी अपनी इस कमजोरी का रोना नहीं रोया, बल्कि इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। पैर खराब होने के बावजूद जब सुहास बैंडमिंटन कोट में उतरते हैं तो बड़े-बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं।

कर्नाटक के छोटे से शहर शिमोगा में जन्मे सुहास एलवाई ने अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखा है। जन्म से ही पैर से विकलांग सुहास शुरुआत से IAS नहीं बनना चाहते थे। बचपन से ही को खेल को लेकर बहद दिलचस्पी रखने थे। उन्हें पिता और परिवार का भरपूर साथ मिला। पैर पूरी तरह फिट नहीं था तो समाज के ताने उन्हें सुनने को मिलते रहे, लेकिन पिता और परिवार चट्टान की तरह उन तानों के सामने खड़े रहे और कभी भी सुहास का हौंसला नहीं टूटने दिया। सुहास के पिता उन्हें सामान्य बच्चों की तरह देखते थे। सुहास का क्रिकेट प्रेम उनके पिता की देन है। परिवार ने उन्हें कभी नहीं रोका, जो मर्जी हुई सुहास ने उस गेम को खेला और पिता ने भी उनसे हमेशा जीत की उम्मीद की। पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, जो सुहास की पढ़ाई शहर-शहर घूमकर होती रही। शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई तो वहीं सुरतकर शहर ने उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी से कम्प्यूटर साइंस में इंजिनियरिंग पूरी की।

बैडमिंटन खिलाड़ी और IAS अधिकारी सुहास एल यथिराज ने रजत पदक अपने नाम किया. एसएल4 वर्ग के फाइनल में सुहास यथिराज को फ्रांस के वर्ल्ड नंबर-1 लुकास मजूर ने 15-21, 21-17, 21-15 से हरा दिया. अपने ग्रुप में तीन में से दो जीत दर्ज करने के बाद सुहास ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था. फिर 38 साल के सुहास ने सेमीफाइल मुकाबले में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 21-9, 21-15 से हराकर रजत पदक पक्का किया.

कृष्णा नागर

कृष्णा नागर का जन्म 12 जनवरी 1999 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था। जब वह 2 साल के थे, तो उन्हें पता चला कि वह बौने हैं। दरअसल, उनकी हड्डी के विकास में कुछ समस्या थी, जिसके चलते उनकी ऊंचाई दूसरों की तरह नहीं बढ़ सकती है। वह आम लड़कों तुलना में काफी छोटे है और उनकी हाइट 4 फीट 2 इंच है। हाइट कम होने की वजह से लोग कृष्णा को ताने देने लगे थे। स्कूल में बच्चे उनके बौनेपन को लेकर मजाक बनाया करते थे। जिसके कारण कृष्णा ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। इस दौरान कृष्णा का परिवार उनकी ढ़ाल बनकर खड़ा रहा और उन्हें कभी भी किसी से कम महसूस नहीं होने दिया। वह लगातार उन्हें खेलने के लिए मोटिवेट करते रहे। ताकि वह खुद को सब बच्चों की तरह ही समझ सके। बचपन में कृष्णा क्रिकेटर बनना चाहते थे। लेकिन लंबाई कम होने की वजह से बैटिंग के दौरान हर बॉल बाउंस होकर उनके सिर के ऊपर से निकल जाती थी। इसके बाद कृष्णा ने क्रिकेट छोड़ वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। इसमें वे काफी अच्छे डिफेंडर बन गए, लेकिन लंबाई की वजह से उसने वॉलीबॉल भी छोड़ना पड़ा। 2017 में जयपुर के एक स्टेडियम में उन्होंने अपने पिता के कहने पर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। और तभी उन्हें पैरा-बैडमिंटन के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने इसी फील्ड में करियर बनने का फैसला किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया. नागर ने पुरुष सिंगल्स एसएच6 फाइनल में हॉन्गकॉन्ग के चू मान काई को 21-17, 16-21, 21-17 से हराया. गौरतलब है कि दूसरी वरीयता प्राप्त कृष्णा नागर ने ग्रुप-बी में अपने दोनों मुकाबलों में जीत हासिल कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था. इसके बाद सेमीफाइनल में नागर ने ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस्टन कूम्ब्स को 21-10, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई.

Cities as engines of economic growth

Rise of the cities herald ascendance of a civilization and its decline is marked by fall of cities and urban culture. Cities are the center of economic production and knowledge production which drives civilization. The central role of the cities can be understood by the Agglomeration economies, which are the benefits accruing from people & firms operating in proximity of each other. The agglomeration benefits are generated due to reduction in costs of raw materials, skill labour and ideas. And some degree of density is also necessary to efficiently share the ever-increasing requirement of hi-tech and expensive infrastructure by reducing per unit cost. The greater variety of goods and services, stronger competition and minimization of cost of interaction in cities leads to massive efficiency gain turning them into economic powerhouse.

Mostly cities start as the center of political power, trade and manufacturing. Industrial production form the core impetus of smaller cities growing into mega cities we see in the modern era. And even though manufacturing tends to move out of the core to the periphery, cities continue to retain their pre-eminent economic positions. Among other things, the major factor is the increasing dependence of economic growth on innovation and knowledge production. And cities are the engines of research and innovation as they tend to be even more highly concentrated than the manufacturing. And studies have shown that given the increasing complexity of innovation, the degree of concentration of innovation in the cities will continue to increase in the foreseeable future. Also, the diversity of city population also gives it a cutting edge in research & innovation.

But some are arguing that intensifying ICT revolution with the advent of 5G, Digital India, AI, 4th industrial revolution has eroded the rationale of the cities as hub of economic activities and innovation. And the post-Covid future will be about decongesting the cities and focusing on the villages, that will supposedly emerge as the drivers of the

economic growth. But none of these prophecies are new. Every technological development has led experts to make such predictions but importance of cities in economic growth has only been reinforced. In 1944 George Orwell said: Reading a batch of rather shallowly optimistic progressive books, I was struck by the automatic way in which people go on repeating certain phrases which were fashionable before 1914. Two great favorites are 'the abolition of distance' and 'the disappearance of frontiers'.

In 1995 The Economist declared that the communication revolution would lead to “death of distance” but if anything, cities have become bigger, denser. While it is true that technological progress has changed our day to day life, but it has not diminished the benefits of proximity. It is specifically true about the knowledge production. Knowledge can be classified in two categories, one that can be codified and distributed everywhere easily and the Tacit knowledge. It is access to tacit knowledge which provides niche comparative advantage.

While technological progress means that successful experiments/projects are published & easily accessed by a wider audience, it is the knowledge of failed attempts which is of importance and is available only in proximity. It is one of the reasons why research and innovation are so densely located. Improvement in ICT and machine learning have given us the ability to automate the most mechanical, routine and low value-added task. But creativity still is purely human endeavor & needs human proximity.

Productivity gains explain most of the economic growth. And productivity growth is driven by knowledge production. Knowledge production itself is a function of population and density as it depends critically on human interactions. Villages or remote towns cannot replace cities as the engines of research and innovation despite improvement and falling cost of connectivity. Arguments to the contrary in the name of Swadeshi are more ideological & political rather than rooted in economic reality. Villages can be integrated into backward supply-chains but by no imagination can they become the drivers of modern economic growth. GDP of city of Tokyo alone is 50% of the India's GDP. Slums of Mumbai are more productive than villages. Villages as center of modern economic growth is anthropological, technological, & economic impossibility.

And cities not only play an economic role but also a pivotal role in social transformation & modernization. Increasing urbanization has accelerated the breakdown of caste-system and economic inefficiency it entailed. Dissolution of the feudal-caste system created free labour & instituted freedom of employment with people no longer artificially restricted to pre-determined jobs. Throughout the history caste-system has weakened whenever urbanization gained strengthen and no wonder that social orthodoxy is uncomfortable with urbanization. It views cities & machines as harbinger of disruption of the orthodox social order. This is especially true of the modern economic growth. But then that is what India needs on a massive scale.

AUTHOR: AASHEERWAD DWIVEDI
ASSISTANT PROFESSOR, SHRI RAM COLLEGE OF COMMERCE

CoWIN: an unheralded success

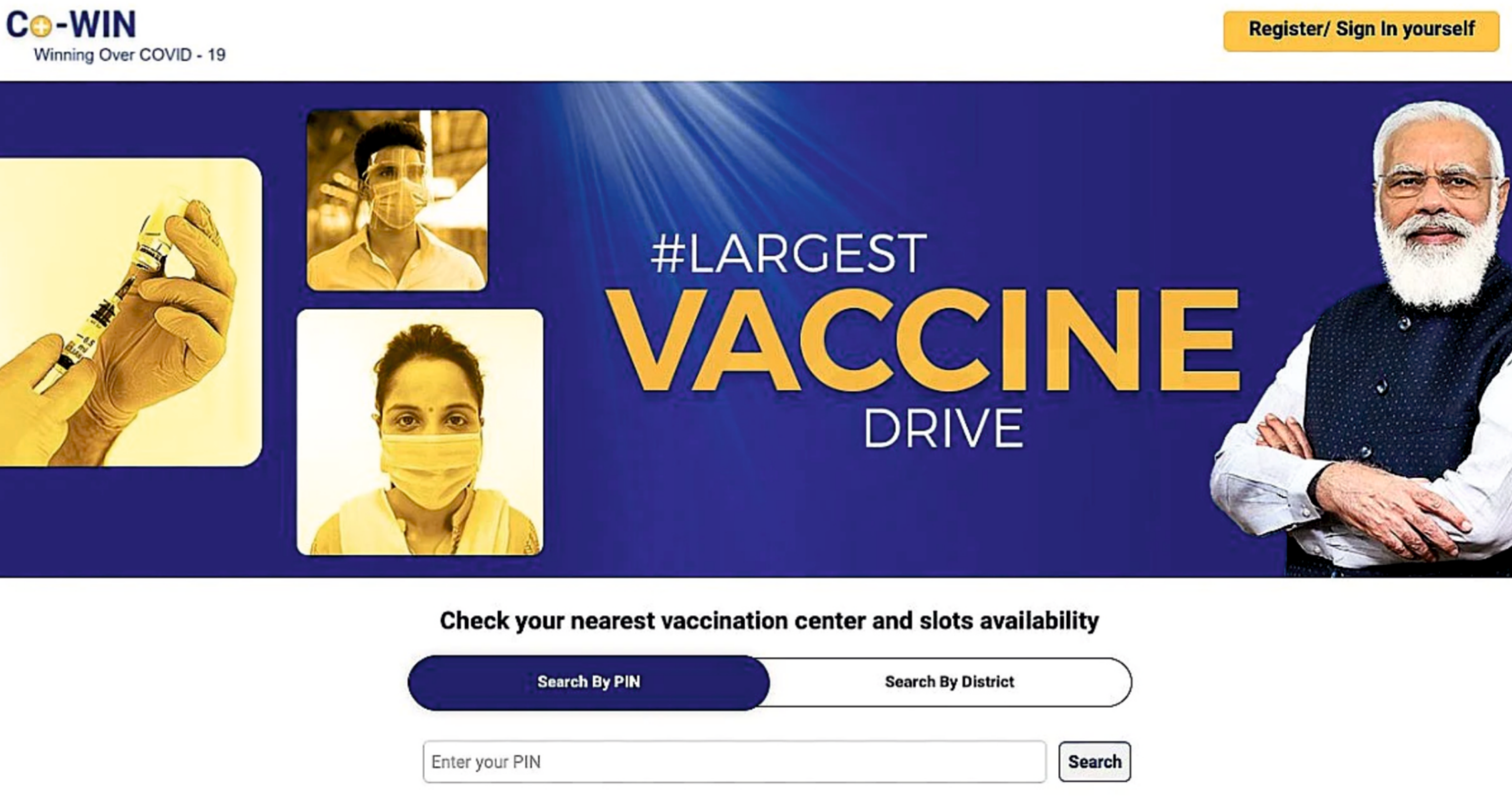

The COVID-19 pandemic has been a shock like none else to system the world over. The subsequent research and creation of a successful vaccine against the disease in record time is a modern-day miracle that promises significant hope for future biomedical research, such as the possibility of vaccines based on the mRNA platform. While the problems associated with the manufacturing of vaccines at a substantial scale are complex, the problems associated with the rollout, distribution and actual administration of vaccines are equally, if not more complex.

In India, the COVID-19 vaccination efforts have been coordinated on the COVID-19 Vaccine Intelligence Network ("CoWIN") platform, which was developed by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) with the United Nations Development Programme (UNDP). The CoWIN platform is an adapted version of the electronic Vaccine Intelligence Network (eVIN) platform that has digitised stocks in 27,000 storage centres and built a capacity of around 37,000 government personnel for vaccine and cold chain logistic management since 2015. This system's adapted form allowed us to manage the distribution, administration and management of the COVID-19 vaccine rollout.

The CoWIN platform functions as an interface for end-users such as us and for National, State and District Level administrators and the vaccinators. It is meant to enable easier planning and scheduling, reduce wastage and increase efficiency. The data regarding session sites, bulk upload of beneficiary data, self-registration session management, monitoring and reporting is also stored on the cloud-based platform. It is meant to be a single solution for administrators, vaccinators, and the general public to interact.

The CoWIN interface also provides an open Application Programming Interface (API), allowing anyone to programme a tool that will alert them if a slot opens up in given parameters. APIs are intermediaries that essentially allow two software to communicate with each other. For example, Google Pay and PhonePe utilise the United Payments Interface (UPI) API to enable payments.

As a result of the CoWIN APIs being open, any person could build a tool that would interact with the CoWIN platform, and they or anyone using the tool can be notified when slots are opened up. Infact, an Open API titled 'Under45.in' was acquired by HealthifyMe, a health and

wellness platform, integrating both notification and slot booking facility (which uses CoWIN). The launch of the KYC-VS API that can give information about vaccination status without compromising the privacy status of individuals by CoWIN facilitates ease of access for both establishments and individuals in establishing safety during the pandemic, as does the simple verification of status by QR code.

While there have been fears that the CoWIN platform increases the digital divide and that the Open APIs would allow persons with advanced technical knowledge to game the system, such fears are quite unsubstantiated. This can be evinced from the 'Government of Indias affidavit in the Supreme Court, according to which on June 23 2021:

- 19.12 crore or 59% of the 32.22 crore beneficiaries were registered on-site.
- 23.12 crore doses for 78% of the 29.68 crore vaccine doses were administered through on-site or walk-in vaccination.
- 74.45% of the vaccination sites are located in rural areas, and 56.24% of the doses administered were at rural centres.
- The doses per million in tribal districts have been higher than the national average.

It indicates that the fears of the digital divide and inaccessibility are likely exaggerated. The high delivery of doses in on-site and walk-in vaccination shows that while direct vaccination slots through CoWIN have been substantial, the States have focussed through outreach via PHCs and through healthcare workers. Even on April 1, 2021 walk-in registrations were four times that of online registrations.

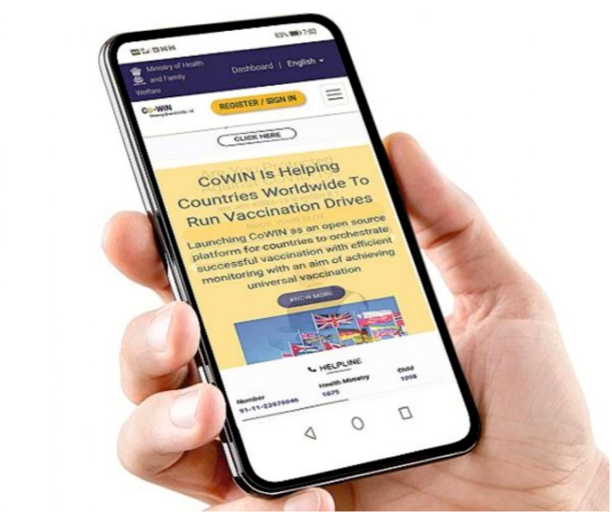

CoWIN also provides on its dashboard information on an hourly “session by session” basis to the level of a district for the past few weeks and for individual vaccine sites daily. This information is a goldmine to understand how well - or how worse - the country's vaccination campaign is going. It also provides information on vaccine reactions (Adverse Events Following Immunisation), Rural v. Urban dosage delivery, registration trends and more.

Overall, it should be noteworthy that such an effort is being made for transparency related to vaccine data. The same platform also generates vaccine certificates and even allows the same to be linked to passports. While privacy concerns have been raised, the CoWIN platform does not mandate the use of Aadhar Card - six other forms of identity, ranging from a driving license to a passport, can be used to register in the platform by the end-user.

This, however, does not mean that only those with ID cards can get vaccinated either. The MoHFW has issued a Standard Operating Procedure for District Level Task Forces to identify such persons and vaccinate them through the use of facilitators for the input of information. (A facilitator for example, can be a Superintendent of an Old Age Home). Around 3.8 lakh persons have been vaccinated without ID cards as of July 2021. With further outreach being done to reach the disabled and bed-ridden, these numbers would have substantially increased by now.

While many faced issues on the initial day when registration was opened up for all those aged above 18, the system had been remarkably resilient. The platform has doubtlessly served us well, and there is no doubt that it can be utilised in the future for other immunisation programmes as well.

The Government has recently announced that the technology will be made open-source, and any country can take advantage of the platform. As many nations step up their COVID-19 vaccination drives, the utility of a vaccine management platform also becomes crucial.

With the launch of the National Health ID System by the Prime Minister recently, there is no doubt that India is attempting to take advantage of the technology and digitalisation to serve the needs of its population. The adoption and use of telemedicine portals such as e-Sanjeevani provide a great outlook for the future of the healthcare sector, combined with the investments made in Higher Educational Institutions. Combined with the PM-JAY or Ayushman Bharat and the enactment of the National Medical Commission Act, 2019, the Government is doubtlessly working for the holistic development of the sector.

The endless potential of technology in this aspect has been harnessed in creating CoWIN, and its success in the vaccination drive augurs well for the future.

As India resumes the export of vaccines, it could also look forward to the export of the CoWIN platform. India has a crucial role to play in the post-pandemic world; with the efficacy of the Chinese vaccine being doubted, India's vaccines and our digital platform can prove the difference for many nations.

AUTHOR: ANANTH KRISHNA SUBHALAKSHMY

Bad Bank

The government has fulfilled another budget announcement by the finance minister Nirmala Sitharaman of establishing a 'Bad Bank' to tackle the intractable problem of non-performing assets. It follows the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), recapitalisation of the public sector banks (PSBs), strengthening of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest (SARFAESI) Act, Debt recovery tribunals and other banking sector reforms. Bad Bank is the logical outcome of the government's strategy of Recognition, Resolution, Recapitalisation and Reform or 4R to reform the banking sector.

The government has set up a National Asset Reconstruction Company (NARCL) to purchase bad loans from the banks. It will acquire them through 15% payment in cash and 85% in Security Receipts, which are now backed by sovereign guaranteed by the government of India. Public sector banks have 51% ownership in the NARCL, which intends to acquire Rs 2 Lakh crore worth of stressed assets. India Debt Resolution Company Ltd. (IDRCL) will act as an asset management company to engage market professionals and turnaround experts. Public-sector banks will have 49% ownership in the IDRCL. NARCL will then sell these assets to Alternate Investment Funds and other buyers.

If it fails to do so or sells at a lower-than-expected price, commercial banks will be paid by invoking the sovereign guarantee from the Rs 30,600 crore fund provided by the government. NARCL is a bank-led institution where no government money will be invested, and no RBI dispensation/forbearance would be required. It will be capitalised through equity from banks and Non-banking Financial Companies (NBFCs) and may raise debt if required.

NARCL-IDRCL structure together is what is being called 'Bad Bank'. It will complement the resolution under the IBC by enabling a single point & faster decision making. It will also enable better value realisation, unlike the present situation where stressed assets are fragmented across various lenders. Also, given that most NPAs with banks are due to large loans to few borrowers in specific industries, NARCL will focus on stressed loan assets above Rs 500 crore, amounting to Rs 2 lakh crore. Transfer of stressed assets will occur under two phases: fully provisioned assets of about Rs 90,000 crore will be transferred under phase I, and remaining assets with lower provisions will be transferred in phase II.

The Bad Bank will play an important role in cleaning up the balance sheet of the commercial banks. It will enable them to get rid of the toxic assets and free up their lending capacity, thus boosting economic activity. It will accelerate the resolution of what is called the twin balance sheet problem, which has been dampening the economic growth of India for long. It will also reduce the burden on the banks by taking over the restructuring and resolution of stressed assets, thus freeing up resources in the banks to focus on their core business. Banks will also benefit from a better valuation and increased ability to raise market capital.

There is a criticism that Bad Bank is simply about privatisation of profits and socialisation of loss and will benefit banks and corporates. Also, such a move is often blamed for exacerbating the moral hazard problem in the banking system, where banks can neglect due diligence in their credit-issuing activities in the expectation of future government intervention. While the argument about moral hazard and incentives may have valid concerns, the criticism that it will only benefit big banks and corporates is misplaced. Restoring the banking system's health will enable better flow of credit in the system and will benefit small and medium scale industries the most who have been facing the squeeze for long as banks were risk-averse and reluctant to lend.

There will be several challenges ahead, especially in determining the correct market value of the stressed assets to be taken over by the Bad Bank and in ensuring speedy restructuring and disposal of such assets. Though the banks can sell security receipts, the real question is to remove the toxic assets from the system itself and not just repair the balance sheet of an individual bank. For this, all the stakeholders will need to work together and complement the government's effort to enact various banking sector reforms. Teamwork and dedicated efforts can yield surprising results. In 2018, just two out of 21 public sector banks were profitable. But in 2021, only two of them reported losses. In this case too, we can expect that realisation in many cases will be more than the acquisition cost.

AUTHOR: NAVNEET PRAKASH, PhD SCHOLAR AT DELHI UNIVERSITY

सेंट्रल विस्टा निजी नही राष्ट्र की सम्पत्ति है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अमेरिकी दौरे से वापस आकर सबको चौंकाते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पँहुचे। ये उनके इस आयु में भी एक नवयुवक की भांति ऊर्जावान व जिज्ञासु होने का प्रमाण है। परन्तु प्रधानमंत्री की यही बातें विपक्ष खासकर कॉंग्रेस को नागवार गुजरती है। कोई प्रधानमंत्री कैसे इतना कर्मठ और जमीन से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने तो ऐसे पीएम दिए देश को, जिन्हें धरती पर ईश्वर का अवतार माना गया। 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा' तक कहा गया। खैर मुद्दा ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए जाने के बाद झूठ और भ्रम की खेती करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए। कोई इसे 'मोदी महल' तो कोई प्रधानमंत्री का आलीशान बंगला करार देते हुए जनता को भ्रमित करने लगा तो कोई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पैसे की बर्बादी करार देने लगा। ठीक वैसे ही जैसे इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के दौरान किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस और उनकी झूठ तरह झूठ की खेती करने वाले अन्य सभी इस मुद्दे को आगे भी तूल देंगे और जनता को भ्रमित करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए झूठ के कारोबारीयों को सच का आईना दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा मोदी जी निजी नही राष्ट्र की संपत्ति है। ये देशहित में कितनी और क्यों जरूरी है ?

दुनिया भर में ऐसे बहुत से देश है जो अपने गुलामी के प्रतीकों को मिटा कर अपने संस्कृति के अनुसार नीतियां स्मारक व पाठ्यक्रम बनाते है ताकि आने वाली पीढ़ियों में आत्मगौरव का बोध कराया जाए।

क्या यह अपमानजनक नहीं है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी और जांबाज सैनिक आज तक घोड़ों के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचों में लगातार काम करते रहे हैं? यह सिलसिला द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हुआ था, जब भारत गुलाम देश था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यही व्यवस्था क्यों बनी रही? अस्तबल और बैरकों के लिए जो अस्थायी ढांचे तैयार किए गए थे, उन्हीं में हमारा रक्षा मंत्रालय कार्यरत क्यों रहा? मजबूरी नहीं, लापरवाही और अनदेखी थी। उपनिवेशवाद की मानसिकता अब भी ज़िंदा थी, लिहाजा जब पुनर्विकास का फैसला लिया गया, तो उसका दुष्प्रचार शुरू हो गया। हालांकि रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों के सचिवालय अलग-अलग और बेहतर भवनों में स्थित रहे। उन्हें अब भी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यह मुद्दा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से उठाया है, जो न जाने कितने व्यापक स्तरों पर ध्वनित हुआ होगा! दूसरा मुद्दा संसद भवन का है। जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, तब 2012 में तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार ने नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा था। उस पर सभी पक्षों की सहमति थी। सबसे अहम कारण बताया गया था कि प्राचीन संसद भवन भूकम्प सरीखी आपदाओं के मद्देनजर सुरक्षित नहीं है। वह भीतर से जर्जर भी होने लगा था। सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो वे कहां बैठेंगे? प्रस्तावित और निर्माणाधीन संसद भवन में एक साथ 1272 सांसद बैठ सकेंगे और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकेंगे। नए भवन में कई और सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

संसद भवन के ही करीब राजपथ है, जहां हर 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवसर पर, सैनिक परेड करते हैं और सांस्कृतिक झांकियों को प्रदर्शित किया जाता है। वे दृश्य हमारी विविधता में एकता को साकार करते हैं। केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विदेशी, अति विशिष्ट सम्मेलनों के सभागार के लिए भी भवनों के पुनर्विकास की जरूरत थी, लिहाजा उनकी परियोजना बनाकर काम शुरू किया गया। रक्षा मंत्रालय के जिन दो परिसरों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, उनमें 7000 से अधिक कर्मचारी काम कर सकेंगे, वहां रक्षा मंत्रालय के दफ्तर आरंभ भी हो गए हैं। अस्थायी अस्तबल ढांचों से मुक्ति मिलनी शुरू हो चुकी है। कमोबेश ऐसी शुरुआत से ही

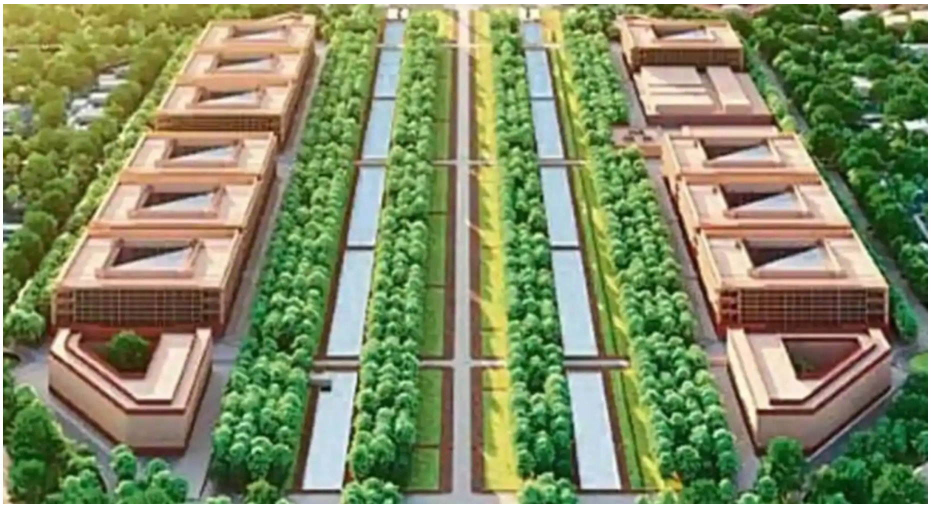

साबित होता है कि सेंट्रल विस्टा के मायने 'मोदी महल' नहीं हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां राजशाही की कोई गुंज़ाइश नहीं है कि किसी शासक का महल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास निर्वाचित प्रधानमंत्री का अधिकृत निवास स्थान होता है। उसी परिसर में प्रधानमंत्री के तौर पर डॉ. मनमोहन सिंह, अटलबिहारी वाजपेयी, आईके गुजराल, देवगौड़ा और उनसे काफी पहले राजीव गांधी तक रहे हैं। गांधी परिवार को तो अच्छी तरह एहसास होगा।

फिर 'मोदी महल' कैसे संभव है? यदि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया प्रधानमंत्री आवास भी बनना है, तो उसे 'मोदी महल' करार क्यों दिया जा रहा है? आवास प्रधानमंत्री मोदी की पैतृक संपत्ति नहीं है और न ही वह हमेशा के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लिहाजा कांग्रेस को ऐसे झूठे, छद्म दुष्प्रचार से बचना चाहिए। इन जुमलों पर वोट नहीं मिला करते। अंततः पार्टी देश और उसकी व्यवस्था का ही अपमान कर रही है। कांग्रेस ने विस्टा के बजट के आंकड़े भी फर्जी पेश किए हैं। रक्षा परिसरों पर करीब 775 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक पूरी परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। यह किस्तों में, साल-दर-साल खर्च किया जाना है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप रहा है। टीके की करीब 76 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। यकीनन बेरोज़गारी भी कुछ बढ़ी है। अर्थव्यवस्था ने कुछ उबरना शुरू किया है। महंगाई थोड़ी है। कई औद्योगिक क्षेत्रों को पूंजीगत सहायता भी देनी है, ताकि उत्पादन पटरी पर लौट सके, लेकिन देश के बुनियादी ढांचे के तहत राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे, सड़कों आदि का निर्माण भी अनिवार्य है। किसी भी क्षेत्र की निरंतरता को कोरोना की वजह से रोका नहीं जा सकता, लिहाजा सेंट्रल विस्टा भी अपरिहार्य है। कुछ गलत हो रहा है, तो विपक्ष उसका खुलासा करे, लेकिन दुष्प्रचार से क्या हासिल होगा? अदालतें भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस को लताड़ लगा चुकी हैं और विस्टा को हरी झंडी दी जा चुकी है।

ऐसे में आवश्यकता इस बात की है देशहित से जुड़े ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स पर भ्रामक प्रचार से देश की जनता को बचाना है और उनके मध्य प्रमाणिकता और तथ्यों के साथ जाना है।

AUTHOR: SAURABH PANDEY

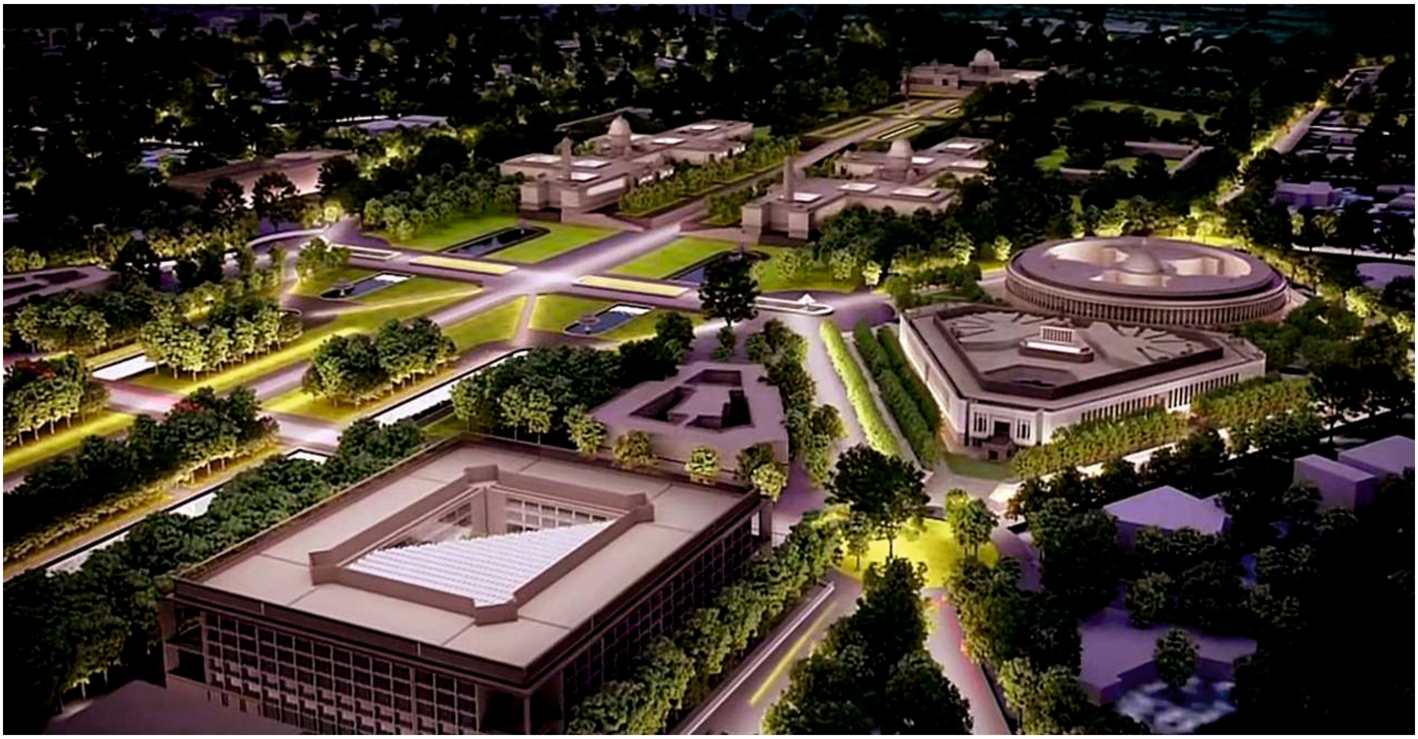

Women Entrepreneurship in New India

The 21st Century is witnessing the vocalisation of demand for equal rights, opportunity and accessibility for women in the economic spheres across the world. Recent scholarships and contemporary research have demonstrated how the forces and structures of social orthodoxy have consciously excluded the recognition of women's labour both in the public and the private, which has resulted in hampering the growth of the economy and the nation-building processes. Due to the social and political changes driven by democracy and changing economic structures, women can now become owners in the economic domain and start their enterprises. Consequently, women have emerged as successful entrepreneurs in various sectors. However, the ratio and narratives of their successes are still limited to certain sectors, and the representation of various sections of women in entrepreneurship is highly inadequate.

Interestingly, the women who succeeded in establishing their enterprises face many difficulties regarding scalability in the market. Various factors that determine lower scalability in the market are common to all entrepreneurs regardless of gender differences, such as policy implementation, accessibility, social environment, family support, property ownership, profitability, product, the role of state and chamber houses and the use of technology and e-resources. However, all these factors have 'gendered translatability', including gender-specific constraints such as family, taboos, culture, lower presense of women in the market and entrepreneurship that impacts both the startup and scalability of existing women entrepreneurship in India.

The pace of economic growth of any country depends not only on the GDP but also on the maximum utilisation of human resources. But, if the orthodox social structures and other social norms hinder 50 per cent of the population from contributing to economic growth, it indicates an obstacle to economic growth and poses a larger question on nation-building.

Modi government has been working towards providing women entrepreneurs with ample opportunities for startup and help their enterprises scale through various schemes such as Standup India various subsidies in different spheres of entrepreneurship.

Prime Minister Narendra Modi, in August 2021, released ₹1,625 crores for women entrepreneurs. He also declared that the loan limit for self-help groups (SHGs) had been raised from ₹10 lakh to ₹20 lakh. The Prime Minister was participating in the 'Atmanirbhar Nari Shakti se Samvad' programme through video conferencing where he spoke to members of women's SHGs associated with Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM). According to PMO, DAY-NRLM aims to mobilise rural poor households into SHGs in a phased manner and provide long-term support to improve their incomes and quality of life. In addition, he released ₹25

crores as seed money for 7,500 SHG members under the PMFME (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) scheme of the ministry of food processing industries and ₹4.13 crore as a fund to 75 FPOs (Farmer Producer Organisations) being promoted under the mission. “The way our sisters served the country through SHGs in Corona is unprecedented. Be it by making masks and sanitisers, delivering food to the needy, awareness work, the contribution of Sakhi groups has been incomparable in every way,” He added that India has at least 420 million Jan Dhan bank accounts, of which 55% are in the name of women. He urged the SHGs to raise awareness about single-use plastic and work on its alternative. He also urged them to take full advantage of the government e-marketplace.

Under Modi Government, two important schemes to support entrepreneurship and self-employment by helping set up micro-enterprises — Standup India and Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY) have women as their biggest beneficiaries. Standup India is a four years old scheme, under which bank loans of Rs 1 lakh to Rs 1 crore are facilitated to at least one scheduled caste or scheduled tribe and one woman borrower per branch of scheduled commercial banks. According to the Ministry of Finance, over 81 per cent of account holders are women. As of February 17, 2020, 73,155 accounts were held by women, while Rs 16712.72 crore has been sanctioned under the Standup India scheme. Out of the sanctioned amount, Rs 9106.13 crore has been disbursed for setting up “greenfield enterprise,” according to the statement by the ministry. Similarly, for PMMY launched in April 2015, out of over Rs 22.53 crore loans sanctioned till January 31, 2020, more than Rs 15.75 crore loans extended to women — 70 per cent of total borrowers. The scheme intends to give up to Rs 10 lakh loans to the non-corporate, non-farm small/micro enterprises classified as Mudra loans given by commercial banks, regional rural banks, small finance banks, microfinance institutions and non-banking financial companies.

The government has been pushing several such schemes to promote women entrepreneurship and increase women participation in trade and business. Atmanirbhar women are at the centre of the vision of the New India of the Prime Minister.

AUTHOR: DR ADITI NARAYANI
ASSISTANT PROFESSOR
MAITREYI COLLEGE
UNIVERSITY OF DELHI

The Challenge of India's Urban Development

Urban development has been one of the most discussed topics in the twenty-first century across the globe. The world has understood the power of cities, ranging from boosting a country's economy to providing green solutions to climate change problems. The majority of the Sustainable Development Goals (SDGs) can be linked to the development of sustainable cities. India is at the forefront of this urban revolution and is transforming at an unmatchable pace. Cities are known to be the engine of a country's economic growth. Cities bring together the workers and industries leading to co-location and co-existing benefits. Cities provide wider economic benefits arising out of the agglomeration externalities. Various studies have indicated a positive relationship between urbanisation and a country's GDP per capita. Indian cities contribute to more than 65 percent of the country's GDP and the number is expected to be more than 75 percent in the coming years. 80 percent of India's tax revenue is generated by urban areas. However, planned and strategic planning of cities and timely development of required infrastructure are the key to unlock the unquantifiable opportunities.

According to the Census of 2011, India was 31 percent urbanised. However, a World Bank report, 2016 claimed that regions with 'urban-like-features' covered more than 55 percent of the land in 2010. The urban population in India is expected to double between 2018 and 2050, from 461 to 877 million. The rise in urban population is majorly due to migration from rural to urban areas in search of a better standard of living, the 'mutation' of rural areas into urban areas and general population increment. The population increment in the existing cities has led to higher human density, irregular and haphazard expansion of city boundaries and proliferation of slums to accommodate the 'urban poor'. The urbanisation process has also put the Urban Local Bodies (ULBs) under tremendous stress. The 74th Amendment of the constitution lays out the responsibilities of the ULBs that give them tasks from providing the basic civic amenities to developing the required infrastructure for urban development. But, the ULBs in India have failed to provide regular water supply, maintain public health, street lighting and sewerage system, and provide for an effective solid

waste management system. The urban facilities like parks, gardens, roads, bridges, etc fail to meet the basic standard requirements. The Covid-19 pandemic has raised serious concerns over the development of cities and higher human densities in a region. However, it is not the density to be blamed, but the lack of infrastructure to support the human density.

The lack of infrastructure has been highlighted by various studies since the beginning of the twenty-first century, but no serious concern was given to it until recently. One of the major reasons behind the shortage of infrastructure is the shortage of finances. Though the constitution laid out the responsibilities, no matching municipal finance list has been provided. This has pushed maximum ULBs in a condition where it has become difficult for them to fund their revenue expenditure (salaries and day-to-day maintenance), leave alone to provide for development activities. The fund crunch has pushed them into a 'poor service-poor revenue' trap. The own sources of revenue of the municipalities have collapsed. Over the years, many of their taxes have been submerged into the state, and central taxes and the municipalities have not received their due compensation for the same. The taxes still in their control, like the property tax, have not been exploited to their potential. The ULBs are completely dependent on state and central governments for grants. On the other hand, the state governments have failed to set up State Finance Commissions (SFSs) on time to study the requirements of the local bodies. Failure to develop proper amenities has affected the revenues of state governments too. The lack of required skills to assess and manage the funds and the inefficient planning of fund mobilisation is the major reason behind the collapse of JNNURM and is now affecting the Smart Cities Mission as well. Both the programmes had to face a fund crunch where the states failed to provide their share in time, forcing the central government to stop its share of the fund. It calls for a long-term sustainable solution to funding urban development.

According to the McKinsey (2010) and High-Powered Expert Committee (HPEC) report on the investment requirements for urban infrastructure services, India would need to spend 3 to 5 percent of the GDP every year to support the demands of the rising urban population. The Budget 2021-22 has taken much-needed steps in this direction. The creation of National Infrastructure Pipeline (NIP) with a target of more than 7,000 projects along with setting up of Development Financial Institution (DFI), which will provide funds for infrastructure and act as a catalyst to attract more investments from foreign and private investors, will ease out the situation for bodies working under acute fiscal stress. The government is also working to monetise the assets of the government, which are lying idle with different ministries and government authorities. This will help the government in raising funds either by selling the land as done by various countries, especially China, or by using it as collateral to borrow money. India should now move on from short-term borrowing to long-term borrowing for 30-35 years at lower interest rates. The central and state governments should also help in reviving the municipal bond market, which has almost collapsed due to the inefficiency of the local bodies, lack of transparency in accounts, and the excessive reliance of local bodies on higher levels of government for funds.

While borrowing is one part of the solution, it is equally important to finding a method to repay the debt without putting a significant burden on the government. The tax Increment Financing (TIF) method is one option that has been practised widely in the US, Canada, Australia, and many European countries. It is a payment mechanism based on the escrowing principle. The method escrows the incremental land and tax values that arise due to the infrastructure development and uses the stream of payment to service the debt used for initial funding. The TIF method can be combined with different Value Capture Financing (VCF) tools and also be incorporated in the Public-Private-Partnership (PPP) models and Build-Operate-Transfer (BOT) models. Some of the commonly used VCF tools that can be combined with the TIF approach are betterment levy, impact fees, sale of land, sale of Floor Space Index (FSI), vacant land tax, land use conversion charge, transfer of development rights, etc. Along with the TIF method and VCF tools, the government needs to initiate a process to strengthen the municipal finances as they will form the backbone of urban development in India. To begin with, they must be compensated for the loss in revenues due to the taxes that have been submerged. The loss of revenue due to GST must be compensated by providing ULBs with a share in the divisible pool of resources. The government should deploy specialists in the ULBs to clean their financial accounts, promote transparency and accountability, and help them in raising money using municipal, infrastructure and green bonds. This money will act as seed money to bring out the ULBs from the 'poor service-poor revenue' trap. State governments need to be strictly advised to set up and follow the recommendations of SFCs and stop the excessive intervention in the functioning of ULBs. These are some of the preliminary actions that are required to initiate planned and strategic development of urban areas to achieve the SDGs, raise the standard of living, boost the economy, eradicate poverty and provide basic amenities to the Indian citizens.

AUTHOR: ABHISHEK MALHOTRA IS A PHD SCHOLAR WORKING IN THE FIELD OF INFRASTRUCTURE FINANCING.

India's New Education Policy 2020 ushers in the dawn of the new era in higher education

"Till date, we've been focusing on 'What to Think' in our education policy. In the NEP, we're focusing on 'How to Think'."

Hon. Prime Minister of India Sh. Narendra Modi

The Ministry of Human Resource Management, Government of India, released its New Education Policy 2020. This policy restructures the convention and rote learning method to include a new, more pragmatic approach to knowledge dissemination. The policy is rooted in the fourth SDG, which aims to "ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all." The policy architects have imbibed the difference between schooling and learning by providing encapsulated pedagogy at different levels.

CURRENT SCENARIO

India has the largest number of school-going children. Moreover, 41 per cent of the population is less than 18 years of age, nearly half of whom are girls. Further, the largest number of children are under lockdown as most schools remain closed, and classes continue through various technologies. Interactive Voice Response, Community Radio, TV, WhatsApp, and various Internet platforms. The state governments are using a wide range of apps for public schools.

Despite the government's efforts to launch apps to reach out to children in rural areas, education is interrupted, specifically for girls. According to government data, the average Gross Enrolment Ratio (GER) of school students at elementary level in 2015-16 was 96.9 per cent, secondary level at 80 per cent, senior secondary level at 56.2 per cent. In 2018-19, the overall GER of students at the elementary level stood at 91.64 per cent, the secondary level at 79.55 per cent and the senior secondary level at 58.56 per cent. A comparison of the annual enrolment data indicates that a significant proportion of children start dropping out of school after Class 8 for various reasons. All the measures taken to bring them back have failed so far. To arrest the trend and ensure 100 per cent GER up to secondary level by 2030, the New Education Policy 2020,

unveiled by the Union government recently, provides for a multi-pronged strategy.

A NEW FOUNDATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

The New Education Policy 2020 deconstructs the old three-level academic structure (primary, 10 +2 years of senior secondary) into four levels (foundation, preparatory, middle and secondary stage) of the new academic structure. The goal is to develop a targeted curriculum for each stage, inclusive of experiential learning, critical thinking, and scientific temper development. The student assessment will be holistic of the overall school experience and not a grade-wise marks based judgment. The curriculum will promote pride in the mother tongue through multilingualism.

The policy revamps the teacher recruitment and training by advanced teacher professional development, opportunities for career growth and participation in academic leadership. Moreover, an imminent focus on the students belonging to the (SEDGs) Socio-Economically Disadvantaged Groups such as gender identities, socio-cultural identities, differently-abled and socio-economic conditions.

The government of India aims to promote the spirit of entrepreneurship from an early start. Therefore, the curriculum is integrated with vocational education at all levels. The purpose is to focus on areas based on skill gap analysis and mapping of local opportunities. The target is to provide vocational education to at least 50% of learners by 2025.

SEAMLESS MOBILITY AMONG DISCIPLINES

One of the important takeaways of the NEP 2020 remains the seamless mobility between arts and sciences, vocational and academic streams, curricular and extra-curricular learning. It aims to eliminate the harmful hierarchy among different areas of learning. More often, students are propelled towards one discipline without being given an option to explore the subjects of the other discipline. The students can, hereon, opt for psychology while studying for pre-med. Education is a public service and not a commercial activity and hence must be considered a fundamental right of every child.

FLEXIBILITY IN HIGHER EDUCATION

The NEP 2020 provides an imaginative and flexible curricular structure that will enable creative combinations and offer multiple entry and exit points, thus removing currently present rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learnings.

The structure and the length of degree programs shall be adjusted accordingly. The undergraduate degree will be of either 3–4 year duration, with multiple exit point options within this period, with appropriate certifications such as a certificate for one year, diploma for completion of two and years and Bachelor's degree for a three-year program.

The higher educational institutions will have the flexibility to offer different designs of Master's program

- A 2- year program with a second year devoted to research for those who have completed 3 — year Bachelor's degree program.
- For students completing 4- year Bachelor's program, there could be a one year Master's program
- Five year integrated Bachelor's/Master's program
- A PhD program will require either a Master's degree or a 4 — year Bachelor's program.

The M.Phil. program shall be discontinued.

The curriculum, continuous assessment, pedagogy are the cornerstone of quality learning. The institutions will integrate their academic plans to accommodate holistic learning. The institutions will provide continuous support and mentorship to students belonging to socio-economically disadvantaged backgrounds.

Online education will provide natural access to quality higher education. Online education will be renewed through a concerted, evidence-based approach while adhering to the strict quality standards.

INDIA'S ROLE AS VISHWA GURU (GLOBAL TEACHER)

The higher educational institutions will facilitate cultural interaction through foreign exchange. Research/teaching collaboration, faculty exchange via MOUs will be initiated to teach and learn from the world. The institutions will facilitate smooth credit transfer to different institutions in India and abroad. The policy provides for foreign universities to establish their campus in India and vice versa.

IMPLEMENTATION OF NEP2020: FROM DAVID TO GOLIATH

Any policy is as good as its implementation. It requires participation from multiple stakeholders and several agencies of the government, along with timelines and plans for review. Most importantly, it requires a humane approach to education. The multiple entry and exit point guard students to be victims of a rigid education system during the detailed crisis. The NEP2020 is highly ambitious, and so is the will of the current leadership.

Dr. Pooja Paswan is an Assistant Professor in the Department of Political Science at Jamia Millia Islamia University, New Delhi, India. (This is an extension of the article published in the American Society of Public Administration PA Times)

AUTHOR: DR POOJA PASWAN. JAMIA MILLIA ISLAMIA. (THIS IS AN EXTENSION OF THE ARTICLE PUBLISHED IN THE AMERICAN SOCIETY OF PUBLIC ADMINISTRATION PA TIMES)

Bhartiya Janata Yuva Morcha

BJYM